RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर

श्री स्वामी रामानंद दासजी महाराज

श्री रामानंद दास अन्नक्षेत्र सेवा ट्रस्ट, तपोवन आश्रम

स्व. पं. पू.1008 श्री रामानन्द जी

तपोवन मंदिर, मोरा गांव, सूरत

वर्ष-12 अंक:244 ता. 17 मार्च 2024, रविवार , कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

लोकसभा चुनाव 2024 : 7 चरणों में होगा मतदान और 4 जून को आएगा रिजल्ट

- चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, मतदान का प्रथम चरण 19 अप्रैल को

नई दिल्ली (एजेंसी)। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि आमचुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को जबकि सातवां अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा। 4 जून को मतगणना कर रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तद्वय ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 19 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को मतगणना की जाएगी और इसी के साथ चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, चौथे चरण का मतदान 13 मई को, पांचवें चरण का मतदान 20 मई को, छठवें चरण का मतदान 25 को और अंतिम सातवें चरण का मतदान 1 जून को मतदान होगा।

इसके मुताबिक पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। इसी प्रकार 26 अप्रैल को दूसरे चरण के अंतर्गत 89 सीटों पर मतदान होगा। जबकि 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठवें चरण में 57 सीटों पर और 1 जून को सातवें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस अवसर पर कहा कि चुनाव में 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिमालय से समुद्र तक और रेगिस्तान से बारिश वाले पूर्वोत्तर तक बनाए जा रहे बूथों पर एक समान सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग वोटर के घर फॉर्म भिजवाए जाएंगे, ताकि वो घर से ही मतदान कर सकें। यदि वो बूथ में आते हैं तो ऐसी स्थित में उनको आयोग के वोलेंटियर सहयोग

करेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में सौ साल से ऊपर के 2.18 लाख मतदाता, जबकि 88.5 लाख मतदाता दिव्यांग हैं। इसी तरह से 85 साल से ऊपर के कुल 82 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.15 करोड़ महिला मतदाता हैं।

चरणबद्ध मतदान की जानकारी

- प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान कराया जाएगा
- द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा
- तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होगा, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा
- चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा
- पंचम चरण में 20 मई को मतदान होगा, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा
- छठवें चरण में 25 मई को मतदान होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा
- अंतिम सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा

मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का शेड्यूल

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया है। 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा। जहां तक राज्यवार चुनाव शेड्यूल की बात है तो 22 ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां महज 1 चरण में चुनाव होगा। 4 राज्य और यूटी में दो चरण में चुनाव संपन्न होंगे जबकि 2 राज्यों में तीन चरण और 3 राज्यों में सभी सात चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। राजस्थान की ही तरह कर्नाटक, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में भी दो चरणों में चुनाव होंगे। दिल्ली में एक चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। दिल्ली में छठवें चरण यानी 25 मई को मतदान होगा।

इन राज्यों के होंगे विधानसभा चुनाव

जिन राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, वहां पर भी मतदान कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा हैं। इन राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होने जा रहा है।

सीएम केजरीवाल कोर्ट में हुए पेश, मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल को ईडी के समन ना मानने के मामले में जमानत मिल गई। बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर सीएम केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से एक इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने सीएम केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।

बीआरएस नेता के कविता कोर्ट में पेश, जांच एजेंसी ने 10 दिन की हिरासत मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच तेलंगाना में बीआरएस नेता के कविता तक पहुंच गई है। ईडी ने कविता को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है। वहीं बीआरएस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। उधर, के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और दिल्ली लाया गया है। वहीं, जब ईडी के कविता के घर कार्रवाई के लिए पहुंची, तब वहां उनके भाई केटीआर से ईडी अफसरों का बहस भी हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि ईडी और बीआरएस नेता केटीआर राव के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। इस प्रकरण के बाद केटीआर की ओर से संदेश जारी किया गया है। इसमें के. कविता और परिवार के सदस्यों ने कहा है कि वे ईडी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे ईडी की अवैध गिरफ्तारी से कानूनी और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निपटने वाले है।

हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा हादसा, फैक्टरी का बॉयलर फटने से दो दर्जन कर्मचारी झुलसे

रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में बॉयलर फटने से कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है लाइफ लॉन्ग नाम की कंपनी के बॉयलर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। यह कंपनी हीरो के स्पेयर पार्ट्स बनाती है।

कांग्रेस, बीआरएस ने तेलंगाना के विकास के सपनों को चकनाचूर किया : प्रधानमंत्री मोदी

हैदराबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर किया है।

उन्होंने नगरकुरनूल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर तेलंगाना में भी ऐसा ही करना होगा। मोदी ने कहा, 'कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर किया हैज्आज

मैंने यहां देखा कि तेलंगाना के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे तीसरी बार मोदी को लाना चाहते हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 400 से अधिक सीटें आने पर अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या गरीबों की जिंदगी में कोई बदलाव आया?

प्रधानमंत्री ने बीआरएस नेता कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।

अमेरिका में अडाणी ग्रुप और गौतम अडाणी के खिलाफ जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका में अडाणी ग्रुप और ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडाणी के खिलाफ जांच की जा रही है। यह जांच इस बात को लेकर हो रही है कि अडाणी ग्रुप, गौतम अडाणी या उनसे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत दी थी? इसके साथ ही गौतम अडाणी के आचरण को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल भी जांच के दायरे में शामिल है। न्यूयॉर्क के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी ऑफिस और वाशिंगटन के न्याय विभाग की फॉड यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अडाणी ग्रुप ने कहा कि हमें हमारे ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी के खिलाफ जारी ऐसी किसी भी जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा बिजनेस ग्रुप उच्च स्तरीय मानकों पर काम करता है। हम भारत सहित अन्य देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधीन हैं और उसका पालन करते हैं।

अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार-रिपोर्ट में बताया गया है कि अटॉर्नी ऑफिस और वाशिंगटन के न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। बता दें कि अमेरिका का कानून अपने अधिकारियों को विदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में क्रॉस एजामिनेशन और जांच करने की अनुमति देता है। हालांकि, उस मामले में अमेरिकी इंवेस्टर्स का पैसा लगा होना चाहिए। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था।

इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली की गई

- राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल बोले
- मोदी-अडानी एक ही है, इन्हें मोडानी कहें

ठाणे (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है।

राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सडक़, सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है। दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बोलते थे कि उन्हें देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में हुए बगावत से दो पार्टियों के विभाजित होने पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक मुफ्त में चले गए?

कोविड-19 से 50 लाख लोगों की मौत

कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के गरीबों की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। उन्होंने दावा किया कि भारत में कोविड-19 से 50 लाख लोगों की मौत हुई।

टीका बनाने वाली कंपनी पीएम को पैसा दे रही थी

राहुल गांधी ने कहा, जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन समारोह में केवल फिल्मी सितारे और शीर्ष उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल किए गए। वहां कोई गरीब मौजूद नहीं था। यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह आदिवासी हैं।

'किसान आंदोलन' के बहाने देश में अराजकता फैलाने की हो रही कोशिश

आरएसएस का बड़ा आरोप, कहा-पंजाब में अलगाववादी आतंकवाद ने फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। आरएसएस ने साथ ही कहा कि अलगावावादी आतंकवाद ने इस आंदोलन के माध्यम से पंजाब में फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया है। आरएसएस ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सैकड़ों माताओं और बहनों के खिलाफ किए गए अत्याचार ने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। संघ ने मणिपुर में जातीय संघर्ष पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे समाज के दो वर्गों- मेइती और कुकी के बीच अविश्वास पैदा हुआ जो गहरे जख्मों का कारण बना। आरएसएस ने ये टिप्पणी शुक्रवार को नागपुर में शुरू हुए संघ के सम्मेलन में होसबाले की ओर से प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में की।

आरएसएस ने संदेशखाली घटना का भी जिक्र किया

रिपोर्ट में आरएसएस ने संदेशखाली घटना का भी जिक्र किया है। उसने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सैकड़ों माताओं-बहनों, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की माताओं-बहनों पर हुए अत्याचार की घटना ने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसी घटनाएं स्वतंत्र भारत के किसी हिस्से में वर्षों से होती आ रही हैं। इसमें कहा गया है कि इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बजाय, वहां (पश्चिम बंगाल) सरकार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया।

नूंह हिंसा का मामला भी उठाया

उसने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं (स्वयंसेवकों) ने संबंधित लोगों के साथ अपने संवा.द के आधार पर स्थिति को संभालने, मनोबल बढ़ाकर समाज को मजबूत करने और मणिपुर में आपसी सहयोग और सह-अस्तित्व का माहौल बनाने का प्रयास किया है। आरएसएस ने कहा कि जहां एक ओर हिंदू समाज में उपयोगी कार्यों के प्रति स्पष्ट जागरुकता और उत्साह है, वहीं कुछ समस्याएं भी राष्ट्र को चुनौती दे रही हैं। उसने कहा कि विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें किसी भी सकारात्मक विकास से कभी खुश नहीं होती हैं।

पंजाब-हरियाणा सीमा पर बैठे हुए हैं किसान

हजारों किसानों ने 13 फरवरी को अपनी मांगों विशेष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करना शुरू कर दिया था। किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, टिकरी और गाजीपुर - में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती देखी गई है। सैकड़ों किसान पिछले एक महीने से अब भी पंजाब-हरियाणा सीमा पर बैठे हुए हैं। 'दिल्ली चलो' मार्च उत्तरी राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा शुरू किए गए लगातार विरोध प्रदर्शन और सड़क नाकेबंदी का दूसरा दौर है।

मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल हुईं राजनीति में सक्रिय, थामा बीजेपी का दामन

नई दिल्ली। मशहूर बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल अब सक्रिय राजनीति करने जा रही हैं। दरअसल उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनुराधा पोंडवाल का बीजेपी में शामिल होना जहां एक ओर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ी सफलता हासिल होना बताया जा रहा है, वहीं स्वयं पोंडवाल ने भाजपा में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया है। भाजपा में शामिल होने के अवसर पर मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं, जिसका सनातन धर्म से गहरा नाता है। अब चूंकि देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं ऐसे में अनुराधा पोंडवाल का भाजपा ज्वाइन करना पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जैसा ही है। आम चुनाव को लेकर भाजपा समेत तमाम दल के स?टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा, कि यह तो मेरा सौभाग ?य है कि मैं आज भाजपा में शामिल हो रही हूं।'

सुप्रसिद्ध गायिका के तौर पर है अनुराधा की पहचान

वालिवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल यूं तो 90 के दशक की मशहूर गायिका हैं, लेकिन आज भी उन्हें हर घर में बेहतरीन गायिका के तौर पर ही पहचाना जाता है। अनुराधा पौंडवाल के भक्ति गीत भी खासे मशहूर हैं। इसे देखते हुए पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव-2024 के लिए स?टार प्रचारक घोषित कर सकती है।

पीएम मोदी के एक वायरल वीडियो ने मचाई धूम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए यह गाना लोगों के बीच तेजी से फैलता जा रहा है। लोग इसे बहुत चाव से सुन रहे हैं और इसे गुनगुना भी रहे हैं। लोगों की जुबां पर गाने का बोल अपना स्थान बनाता जा रहा है। इसे सुनने वाले इसकी सराहना भी कर रहे हैं। गाने के जरिये जिन तथ्यों को बताया गया है, उस पर लोग अपनी सहमति भी प्रकट कर रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा भारत मेरा परिवार अभियान की कड़ी में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के बीच इसे काफी पसंद किया जा रहा हैं। लोग इसके गाने को खूब सुन रहे हैं। गाने का बोल मैं मोदी का परिवार हूं है। बता दें कि है कि तीन मार्च को पटना में एक रैली में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा था कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, वो परिवारवाद पर क्या बोल सकते हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि देश की 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। इसके बाद तो मै हूं मोदी का परिवार नाम का अभियान ही चल पड़ा। देश भर के लोगों ने पीएम मोदी को अपना परिवार बताना शुरू कर दिया। पीएम मोदी को अपना परिवार बताने की कड़ी में ही यह नया वीडियो वायरल हो रहा है।

सेवा भारती को बदनाम करने की साजिश, यूट्यूबर पर 50 लाख का जुर्माना , मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

चेन्नई । मद्रास हाई कोर्ट ने आरएसएस से जुड़े संगठन सेवा भारती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक यूट्यूबर पर 50 लाख का जुर्माना बतौर हर्जाना ठोका है। इतना ही नहीं अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत ने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है और ना ही आंख बंद कर रह सकती है। जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता और अधिकार का उपयोग दूसरों की गोपनीयता पर हमला करने या उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कुमार ने फैसले में लिखा, केवल, अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने, कोई दूसरों की निजता में दखल देकर साक्षात्कार नहीं कर सकता, कानून किसी यूट्यूबर और सोशल मीडिया को दूसरों की प्रतिष्ठा खराब करने की इजाजत नहीं देता है। साथ ही कोर्ट ने यूट्यूबर सुरेंद्र उर्फ नाथिकन को सेवा भारती ट्रस्ट को 50 लाख का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है। दरअसल, यूट्यूबर ने दो ईसाई पुरुषों, पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमिलनाडु की सेवा भारती ट्रस्ट के तार जोड़े थे और ट्रस्ट पर कई अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ सेवा भारती ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर मुआवजे की मांग की थी। साथ ही ट्रस्ट ने अदालत से मांग की थी कि वह यूट्यूबर को उसके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने का निर्देश दे। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर प्रसारित बयानों का इस्तेमाल ब्लैक मेल करने के एक उपकरण के रूप में करने लगे हैं, इस चलन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। वहीं सेवा भारती ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि जयराज और बेनिक्स की मौत से उसका कोई लेना-देना नहीं रहा है और यह ज्ञात तथ्य है कि दोनों की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी।

भारत ने पाक सीमा पर बढ़ाई आर्मी, हवा में तैनात होंगे टैंक

नई दिल्ली। पाकिस्तान से लगती सीमा पर जल्द ही हेवी ड्यूटी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे की तैनाती की जाएगी । इससे पहले इंडियन आर्मी ने पश्चिमी कमान में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य पोस्ट जोधपुर में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। भारतीय सेना ने हेवी ड्यूटी और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को बढ़ाया है। स्क्वाड्रन के अस्तित्व में आने से सेना का पश्चिमी कमान और ज्यादा मजबूत होगा और उसकी युद्धक क्षमता भी बढ़ेगी। बता दें कि आर्मी के वेस्टर्न कमान में अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका से इसकी पहली खेप फरवरी 2024 में मिलनी थी, लेकिन उसमें देरी हुई है। अब अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मई में मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सीमा पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। देश के पश्चिमी सीमा पर 'हवा में टैंक' तैनात करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि इस बार गर्मी के मौसम में इसे पूरा कर लिया जाएगा। बॉर्डर पर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और सेना की स्ट्रैटजिक प्लानिंग से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मचना तय है। भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर समझौता किया है। तकरीबन 5,691 करोड़ रुपये की इस डील के तहत बोइंग सेना को 6 हेलीकॉप्टर देगा। फरवरी 2020 में रक्षा खरीद पर सहमति बनी थी। आर्मी के एविएशन डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी ने बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति फरवरी में ही शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इसमें कुछ देरी हुई है। भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की जा चुकी है। वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी कंपनी के साथ 13, 952 करोड़ रुपये का करार किया था।

हैती में फंसे 90 भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने शुरु किए प्रयास

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैरेबियाई देश हैती पर अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। जिसके कारण कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों का घर से निकलना कठिन हो गया है ऐसे में 90 भारतीय भी हैती में फंसे हुए हैं। इन्हे निकालने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रयास शुरु कर दिए है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हैती में 75 से 90 भारतीय मौजूद हैं जिनमें से लगभग 60 ने जरूरत पड़ने पर भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हैती में 75 से 90 भारतीय हैं और उनमें से लगभग 60 ने ÷जरूरत पड़ने पर वापस आने÷ के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराया हैय उन्होंने कहा, ÷हम सभी को निकालने के लिए तैयार हैं। भारतीय पक्ष ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कोलकाता स्थित संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 30 से अधिक ननों से संपर्क किया है, जो हैती में हैं, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे सभी वापस लौटने का विकल्प चुनेंगे या नहीं। भारत का हैती में कोई दूतावास नहीं है और देश की स्थिति की निगरानी डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में भारतीय मिशन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है। सैंटो डोमिंगो में भारतीय दूतावास, जिसे हैती की भी मान्यता प्राप्त है, हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस और देश के अन्य हिस्सों में सभी भारतीयों के संपर्क में है।

कैरेबियाई राष्ट्र हैती अपराधियों के कब्जे में है। हैती की राजधानी और अन्य क्षेत्रों पर आपराधिक गिरोहों का कब्जा हो गया है। सुरक्षा की स्थिति में गिरावट के बाद हैती में फंसे 90 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए तैयार है। हैती में सरकारी संरचनाओं और सामाजिक व्यवस्था के पतन के कगार पर होने के कारण संकटग्रस्त प्रधान मंत्री एरियल हेनरी ने अपना पद छोड़ने की पेशकश की है। इस बीच गवर्निंग काउंसिल की स्थापना के लिए कैरेबियन समुदाय और कॉमन मार्केट ने बातचीत शुरू की है।हाईटियन राजनेताओं और पार्टियों के बीच झगड़े के कारण एक संक्रमणकालीन परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव मुश्किल में पड़ गया है। कैरीकॉम राज्यों के नेताओं ने जमैका में एक बैठक के बाद परिषद बनाने की योजना का खुलासा किया, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भाग लिया। हैती के प्रधानमंत्री हेनरी ने परिषद की स्थापना होते ही पद छोड़ने का वादा किया है।

फडणवीस का दावा : बाला साहेब का बेटा किसी भी सूरत में सीएए का विरोध नहीं कर सकता

मुंबई। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब का बेटा किसी भी सूरत में सीएए का विरोध नहीं कर सकता है। फडणवीस ने हिंदूवादी दिवंगत नेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को याद करते हुए उनके बेटे उद्धव पर जोरदार हमला बोला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा, उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया है। मुझे यह समझना मुश्किल हो रहा है कि बाल ठाकरे का बेटा ऐसा कर सकता है।उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार मुंबई में उन चीजों को ठीक करने के लिए मजबूर है जिन्हें वर्षों पहले ठीक किया जाना चाहिए था। फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे को मुंबई के लोगों ने कई मौके दिए लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। शहर में उनके द्वारा एक भी प्रतिष्ठित काम नहीं किया गया या बनाया नहीं गया। एक इंटरव्यू में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के मोदी विरोधी रुख के लिए उनकी आलोचना की और लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह कोई प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी ओर से उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि वह अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अब छद्म धर्मनिरपेक्ष और तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त हैं।फडणवीस ने सीट बंटवारे, महाराष्ट्र और मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास, संभावित नए सहयोगियों और पिछली सरकार की कमियों के बारे में खुलकर बात की है।

कांग्रेस व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है: खरगे

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित करने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। ये वादे 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए शनिवार को पार्टी द्वारा घोषित पांच अन्य गारंटियों में शामिल हैं।

खरगे ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत आने वाली गारंटी गिनाते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों व समुदायों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी और शासन से संबंधित संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक नीति देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

खरगे ने कहा, 'कांग्रेस यह गारंटी भी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित करेगीज50 प्रतिशत सीमा बढ़ाकर 60, 65 की जा सकती है। तमिलनाडु की तरह, उन्होंने जो किया, हम भी करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस एससी और एसटी की विशेष घटक योजना को कानून द्वारा पुनर्जीवित व लागू करने की गारंटी देती है। खरगे ने कहा कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में यह कदम पहले ही उठाया जा चुका है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल में हल करने और खारिज किए गए दावों की छह महीने के अंदर समीक्षा के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की गारंटी देती है। खरगे ने कहा, 'अपनी धरती, अपना राज÷ के तहत कांग्रेस लघु वन उपज के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी भी बढ़ाएगी। पार्टी आदिवासी भाई-बहनों को स्वशासन और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।'

पार्टी ने कहा कि कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं। खरगे ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस ने 'किसान न्याय', 'युवा न्याय' और 'महिला न्याय' के तहत 15 गारंटियों की घोषणा की है।

लोकसभा चुनाव के लिये तैयार, लोकतंत्र के भविष्य का होगा फैसला : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शनिवार को कहा कि वह इस चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है तथा यह चुनाव आम नहीं, बल्कि खास है क्योंकि इसमें देश के लोकतंत्र के भविष्य का फैसला होगा। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ''चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। यह चुनाव आम नहीं है। यह चुनाव फैसला करेगा कि यह देश और लोकतंत्र मजदूर किसान के कंधों पर चलेगा या कुछ उद्योगपतियों के कंधों पर चलेगा।'' उन्होंने कहा, ''इस चुनाव से तय होगा कि देश बाबासाहेब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए यह एक आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है।''

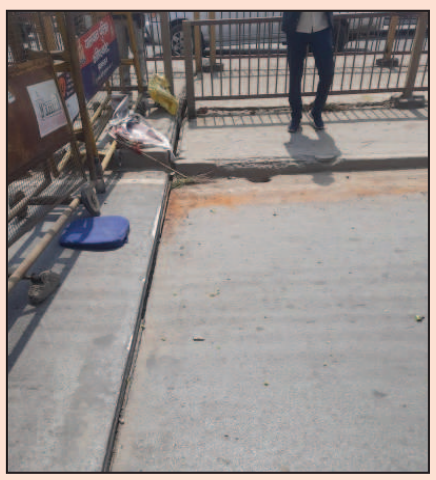

संवाददाता लक्ष्मीकांत पाण्डेय, प्रयागराज। प्रयागराज के संगम तट पर बने शास्त्री पुल का पिलर नबर 28 छतीग्रस्त होने के कारण बडा हादसा होते होते बच गया रही बात वाराणासी से प्रयागराज हनुमानगंज हण्डिया से आने जाने वाले लोगो को भारी जाम का काफी दिक्कतो का सामना करना पडा वही उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पी डब्ल्यू डी विभाग को मिले शास्त्री पुल की रख रखाव की जम्मिदारी पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नितिन गडकरी अपने विभाग के कार्यो पर भरोसा करते है वहा प्रयागराज का शास्त्री पुल सवाल खडा कर रहा वही साथ ही पुल से रोज आने जाने लोगो का कहना कि हाल ही मे कुभं का मेला खत्म हुआ है अगर यह मेले के दौरान होता तो बहुत बडे हादसा घटित हो सकती थी साथ ही आगामी महा कुम्भं की तैयारी जोर-शोर से चल रही है फिलहाल सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग प्रयागराज के अधिकारीगण मौके पर पहुंच जल्द से जल्द शास्त्री पुल की मरम्मत कार्य करने का आदेश दिए ।

अधिवक्ता परिषद हंण्डिया तहसील के शुभाष कुमार तिवारी अध्यक्ष बने एव वेद प्रकाश ने मंत्री पद पर किया कब्जा

संवाददाता लक्ष्मीकांत पाण्डेय, प्रयागराज। हण्डिया अधिवक्ता परिषद चुनाव के दौरान पुरे दिन गरमी गरमा एव शोर शराबे के बीच चला वही पुरे दिन अधिवक्ताओ के बीच अध्यक्ष और मंत्री समेत कई अन्य पदो पर अपने अपने प्रत्याशियो का दबदबा कायम रखने का हल्ला होता रहा अधिवक्ता परिषद का चुनाव विद्वान अधिवक्ताओ ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री पद पर अपना अपना किस्मत अजमाया जिसमे न्यायालय अधिवक्ता परिषद तहसील हण्डिया चुनाव मे निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार मिश्र (बबलू मिश्र)एल्डर कमेटी के चेयरमैन महेंद्र कुमार सिंह, कुवर देवेन्द्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र त्रिपाठी निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र पति मिश्र आदि सदस्यो के निगरानी मे सम्पन्न हुआ दस बसे 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता हुआ फाइनल परिणाम आना प्रारम्भ हुआ जिसमे कुल मत 999 मे से 847 मत पडा जिसमे कोषाध्यक्ष के पदपर गोपाल बाबू यादव को 394 मत और सुशील कुमार पांडेय को 445 मतो से विजयी घोषित हुए ही मंत्री पद अजय कुमार सिंह 239 मत देवेन्द्र कुमार बिरौरा 18 6 मत लक्ष्न प्रसाद 49 मत वही वेद प्रकाश शुक्ल 365 पद हासिल कर मंत्री पद पर अपना दबदबा कायम रखा वही उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण राज यादव 489 मत निरज कुमार शुक्ल 446 मत राकेश कुमार यादव 523 मत हासिल कर जीत दर्ज किया वही अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार मिश्र ने 163 मत समरजीत यादव 341 मत और शुभाष कुमार तिवारी ने 343 मत हासिल कर अध्यक्ष पद पर अपना दबदबा कायम रखा ।

पृथ्वी का लगभग 19 प्रतिशत भाग बंजर

-10 प्रतिशत भाग को ग्लेशियरों ने ढंका हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी ओर इन जीवनदायी पेड़ों को लगातार उजाड़ा जा रहा है। दुनियाभर के देशों से जंगल कम हो रहे हैं।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में वो कौन सा देश है, जहां सबसे अधिक पेड़ हैं? भूवैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक पृथ्वी का लगभग 19 प्रतिशत भाग बंजर है, जबकि 10 प्रतिशत भाग को ग्लेशियरों ने ढंका हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे हिस्से भी हैं, जहां पर रेत के टीले, रेगिस्तान, चट्टानी भूमि और शुष्क नमक वाले क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, दुनिया में कुल रहने योग्य जगह का लगभग 38 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा है। यह पृथ्वी की कुल भूमि के 26 प्रतिशत के बराबर है।ऐसे में फिर से सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका और अमेरिका पेड़ों के मामले में सबसे आगे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हैं। इस धरती पर रूस वो देश है, जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ मौजूद हैं।

जानकारी के मुताबिक, रूस में लगभग 815 मिलियन हेक्टेयर वन हैं, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक वृक्ष-घना देश बनाता है। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि दुनिया में कुल कितने पेड़ हैं? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन पेड़ हैं।

दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन के जंगल लगभग 9.8 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। अमेजन के इस जंगल को विश्व में सबसे बड़ा वर्षावन माना जाता है। यह विश्व के कुल वर्षावन का एक तिहाई भाग घेरता है।अमेजन का यह वर्षावन कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें कोलंबिया, पेरू और ब्राजील सहित नौ दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं।

रिसर्च से पता चला है कि अमेजन वर्षावन में दुनिया की लगभग 10 प्रतिशत जैव विविधता शामिल है, जिसमें जानवर, पौधे और अन्य जीवित चीजें शामिल हैं। मालूम हो कि वैज्ञानिक पेड़ों को मानव जाति का सबसे लाभकारी मित्र बताते हैं। लेकिन इंसानों ने इन पेड़ों को परोपकारी का उचित दर्जा नहीं दिया है। शायद यही वजह है कि पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस विनाश ने पूरी दुनिया को रसातल के कगार पर पहुंचा दिया है।

चुनावी बॉण्ड घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो स्वतंत्र जांच, कांग्रेस पार्टी की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि चुनावी बॉण्ड घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में सरकार का मतलब जितना चंदा, उतना हक है। कांग्रेस नेता रमेश ने पोस्ट किया, चुनावी बॉण्ड पर डेटा सामने आने के बाद पहले विश्लेषण में भाजपा की चार भ्रष्ट नीति - चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो और फर्जी कंपनी-डकैत संगनी सामने आई थी। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा, भारत के कॉरपोरेट से हजारों करोड़ रुपये की उगाही और वसूली की गई है। हजारों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति लूटी गई है। उन्होंने दावा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों ने भारी मात्रा में चंदा दिया है। उदाहरण के लिए मेघा इंजीनियरिंग, तेलंगाना में कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर काम कर रही थी। मेघा ने मेडीगड्डा बैराज के कुछ हिस्से का निर्माण किया, जो इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा हुआ कि बैराज डूबने लगा, जिससे करदाताओं का एक लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। उनके मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में इस तरह बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के खराब होने कई उदाहरण सामने आए हैं, ऐसा ही एक और उदाहरण गुजरात का मोरबी है।

पाकिस्तान छोड़कर आए हिंदुओं को नागरिकता क्यों नहीं देना चाहिए: अमित शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता क्यों नहीं देनी चाहिए। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 23 प्रतिशत थी। आज घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई है। ये हिंदु गए कहां। सबको पता है कि या तो मार दिए गए या जबरियां धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कुछ लोग अत्याचार से परेशान होकर भारत आ गए। क्या ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए। शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पीओके को लेकर अपनी पार्टी और केंद्र सरकार का स्टैंड साफ करते हुए शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है। इसलिए वहां के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हमारे लोग हैं। एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने देश के विभाजन को गलत बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जा रहे सवालों पर शाह ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है की चुनावी बॉन्ड से भाजपा को फायदा हुआ है, जबकि हकीकत इससे उलट है। भाजपा के सांसद ज्यादा है लेकिन उसे केवल छह हजार करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, जबकि विपक्ष के सांसद कम होने के बावजूद उनको कई गुना ज्यादा मूल्य के बॉन्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड का चिट्ठा खुलेगा तो विपक्ष परेशानी में आएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व खत्म करने के लिए लाया गया था। पर उच्चतम न्यायालय जो फैसला देती है, वो सभी को मानना होता है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कोई उनको ये समझा दे कि चुनावी बॉन्ड आने से पहले चंदा कैसे आता था, बॉन्ड से चंदा कैसे आता है? अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड खरीदते हैं और राजनीति पार्टियों को देते हैं। उन्होंने कहा, इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया है। उन्होंने कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि जो नकदी में चंदा आता था, उसमें किसका नाम सामने आया है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बॉन्ड से भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि वह सत्ता में है। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी ने बयान दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का

बड़ा जरिया चुनावी बॉन्ड है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं राहुल गांधी को ये लिखकर कौन देता है। भाजपा को करीब छह हजार करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। कुल बॉन्ड 20 हजार करोड़ के हैं तो 14 हजार के बॉन्ड कहां गए?

कनाडा में भारतीय परिवार की मौत

ब्रैंपटन । कनाडा के ओंटारियो प्रांत में भारतीय परिवार के घर में आग लगने से 3 सदस्यों की मौत हो गई। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस को शक है कि घर में आग लगाई। उनका कहना है कि आग लगना एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। पुलिस ने शनिवार को कहा- ब्रैंपटन शहर में स्थित एक घर में 7 मार्च को आग लगी थी। यहां आग बुझाए जाने के बाद मानव अवशेष मिले थे। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ था कि कितने लोग जलकर मरे हैं। 15 मार्च को मानव अवशेषों की पहचान भारतीय परिवार के तीन सदस्यों के रूप में हुई। पुलिस अफसर टैरिन यंग ने कहा- आग में झुलसकर राजीव वारिकू, पत्नी शिल्पा कोठा और 16 साल की बेटी महेक वारिकू की मौत हो गई। आग लगने से पहले तीनों घर में ही मौजूद थे।

नोबेल पुरस्कार विजेता पर मुकदमा दर्ज

बीजिंग । चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार मो यान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा चीन के राष्ट्रवादी ब्लॉगर माने जाने वाले वू वानझेंग ने दायर कराया है। वू का आरोप है कि मो यान ने अपनी किताब में चीन की सेना की आलोचना की है और जापान के सैनिकों को गौरवशाली परिपेक्ष्य में दिखाया। मो यान की यह फिक्शनल किताब जापान के चीन पर हमले के समय पर आधारित है। वू वानझेंग सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अक्सर राष्ट्रवादी मुद्दों पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। वू वानझेंग ने मुकदमे में मो यान से 1.5 अरब युआन का हर्जाना मांगा है। यह हर्जाना हर चीनी नागरिक के लिए एक युआन के आधार पर मांगा गया है और साथ ही मुकदमे में मो यान से माफी की मांग भी की गई है। वू वानझेंग ने ये भी मांग की है कि कथित विवादित किताब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। हालांकि चीन की किसी अदालत ने अभी तक वू वानझेंग के मुकदमे को स्वीकार नहीं किया है।

क्रोएशिया में संसदीय चुनाव 17 अप्रैल को

बेलग्रेड। क्रोएशिया में संसदीय चुनाव 17 अप्रैल को होने है। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक के प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि श्री मिलानोविक ने देश में 17 अप्रैल को संसदीय चुनाव निर्धारित किए हैं। बयान के अनुसार क्रोएशियाई सबोर के सांसदों ने आखिरी बैठक में क्रोएशिया साम्राज्य की 1100वीं वर्षगांठ की तैयारियों की समीक्षा की, कई अंतरराष्ट्रीय संधियों की पुष्टि की, प्राकृतिक गैस और अन्य ईंधन पर वैट दर में कटौती को बढ़ाया, कई आर्थिक उपायों पर चर्चा की और संसद को भंग करने के लिए मतदान किया। प्रशासन द्वारा प्रकाशित श्री मिलानोविक के निर्णय में कहा गया, क्रोएशियाई सबोर के लिए सांसदों का चुनाव बुधवार, 17 अप्रैल, 2024 को होगा।

अमेरिका ने इटली को एक हथियार सौदे की मंजूरी दी

वाशिंगटन । अमेरिका ने इटली के साथ एक हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। विदेश विभाग ने नौ करोड 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एआईएम-9एक्स साइडवाइंडर मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की इटली सरकार को संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इटली ने 88 एआईएम-9एक्स साइडवाइंडर ब्लॉक टू प्लस टैक्टिकल मिसाइलें, चार एआईएम-9 एक्स ब्लॉक टू प्लस टैक्टिकल गाइडेंस यूनिट, आठ एआईएम-9 एक्स कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल (सीएटीएम) और दो एआईएम-9एक्स सीएटीएम मार्गदर्शन इकाइयाँ, सक्रिय ऑप्टिकल लक्ष्य डिटेक्टरों, कार्मिक प्रशिक्षण और रसद सहायता सेवाओं जैसे अतिरिक्त उपकरणों के साथ खरीदने का अनुरोध किया है। बयान में कहा गया यह प्रस्तावित बिक्री नाटो सहयोगी की सुरक्षा में सुधार करके अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी जो यूरोप में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए एक ताकत है तथा इससे क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा।

यूएनएससी में गाजा पर अमेरिका प्रस्ताव पर बातचीत जारी

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में राजनयिकों की गाजा पर अमेरिका की ओर से तैयार प्रस्ताव पर बातचीत जारी है, लेकिन प्रस्ताव में तत्काल युद्धविराम की मांग के महत्व को कम कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पॉलींस्की ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग वाले प्रस्तावों को विफल करने के लिए पिछले पांच महीनों में तीन बार सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। श्री पॉलींस्की ने कहा कि सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य तत्काल युद्धविराम की मांग और राफा में इजरायली अभियान का विरोध करने वाले प्रस्ताव के प्रयासों में अमेरिका बाधा डाल रहा है। अमेरिकी प्रस्ताव में इजरायली अभियान का उल्लेख करते हुए कहा गया राफा में जमीनी हमले से नागरिकों को और अधिक नुकसान होगा तथा संभावित रूप से पड़ोसी देशों में उनका विस्थापन भी होगा। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गाजा पट्टी में अब तक करीब 31,300 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा, 24 नवंबर को, कतर ने इजरायल और हमास के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों और बंधकों की अदला-बदली के साथ-साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के वितरण पर एक समझौते में मध्यस्थता की।

हमास और इजराइल के बीच युद्धविराम की संभावना

- इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर हो सकता है सहमत

तेल अवीव । हमास और इजराइल के बीच युद्धविराम की संभावना बढ़ गई है। दोनों पक्ष अपनी पिछली मांगों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। हमास जहां युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने की अपनी मांग की जगह इसे छह सप्ताह के लिए रोकने पर सहमत हो गया है, वहीं इज़राइल 1000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर लगभग तैयार हो गया है। इनमें से 100 पर हत्या सहित गंभीर अपराधों का आरोप है। युद्ध विराम के लिए पिछले दो दिनों में दोहा, काहिरा और पेरिस में वार्ताकारों के बीच कई बैठकें हुईं। इजराइली खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि कतर ने हमास नेतृत्व को सूचित किया है कि अगर वे अपनी अनुचित मांगों से पीछे नहीं हटते हैं, तो कतर उनके नेताओं को अपने देश से निर्वासित करने में संकोच नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक हमास 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के बदले में सैनिकों सहित सभी इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। इजराइली खुफिया एजेंसियों ने सरकार को सूचित किया है कि गाजा में शेष 134 इजराइली बंधकों में से 32 की मौत हो गई है। इजराइली प्रधान मंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के बदले में हमास शेष 102 बंधकों को रिहा करेगा और 32 बंधकों के शवों को इजराइल भेजेगा।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा तोहफे में दी कार लिमोजिन में सवारी करते नजर आये किम जोंग उन

सियोल। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा भेंट में दी लग्जरी कार लिमोजिन में सफर किया। किम की बहन ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कार की ''विशेषताओं'' और दोनों देशों के बीच गहरे हो रहे द्विपक्षीय संबंधों की प्रशंसा की। पुतिन ने फरवरी में किम के लिए महंगी ऑरस सीनट लिमोजिन भेजी थी। उन्होंने सितंबर में रूस में एक शिखर सम्मेलन के लिए हुई मुलाकात के दौरान यह कार उत्तर कोरियाई नेता को दिखायी थी। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस कार को भेजने से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव का उद्देश्य उत्तर कोरिया को लग्जरी सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाकर उस पर अपने परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को छोड़ने के लिए दबाव बनाना है। सरकारी मीडिया में शनिवार को आए बयान में किम की बहन और वरिष्ठ अधिकारी किम यो जोंग ने कहा कि उनके भाई ने एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार लिमोजिन में सफर किया। उन्होंने कहा, ''किम जोंग उन का रूसी फेडरेशन के राष्ट्रपति द्वारा उपहार स्वरूप भेजी निजी कार का इस्तेमाल करना उत्तर कोरिया-रूस के बीच मित्रता का स्पष्ट प्रमाण है जो एक नए उच्च स्तर पर व्यापक रूप से विकसित हो रही है।''

क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीपीबीडी) ग्रोबोगन द्वारा प्रदान की गई यह तस्वीर ग्रोबोगन रीजेंसी, मध्य जावा, इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ वाले क्षेत्र को दिखाती है।

राजनीति से ऊबे कनाडाई पीएम बोले- ये पागलपन से भरी नौकरी है

टोरंटो। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए अगले साल यानी अक्टूबर 2025 तक चुनाव होना है। इसके लिए हुए हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव्स के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। सर्वे की मानें तो कनाडा के मतदाता ट्रूडो से ऊब चुके हैं। ट्रूडो बतौर प्रधानमंत्री अपनी नौकरी से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि यह एक पागलपन भरी नौकरी है और वे इसे छोड़ने के बारे में सोच रहे थे।

हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अगले चुनाव तक पद पर बने रहेंगे। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा चुनावों में बुरी तरह से पिछड़ रही है। ट्रूडो ने पहली बार नवंबर 2015 में पदभार संभाला था। तमाम सर्वे में हो रही हार की भविष्यवाणी के बीच ट्रूडो ने एक लंबे इंटरव्यू में फ्रांसीसी भाषा के ब्रॉडकास्टर रेडियो-कनाडा को बताया, मैं जो आज हूं वह शख्स कभी नहीं बन पाता। इसलिए इस अहम मोड़ पर मैं ये लड़ाई नहीं छोड़ सकता हूं।जब उनसे पूछा गया कि क्या वह राजनीति छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन छोड़ने के बारे में सोचता हूं। यह एक पागलपन भरा काम है जो मैं कर रहा हूं। व्यक्तिगत बलिदान दे रहा हूं... बेशक, यह बहुत मुश्किल है। पिछले साल ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ने घोषणा की थी कि वे 18 साल की शादी के बाद अलग हो रहे हैं। ट्रूडो ने कहा, हमेशा ये बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं लोकप्रिय होने के लिए राजनीति में नहीं आया, व्यक्तिगत कारणों से नहीं, (बल्कि) क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूं और मुझे पता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ है।

अमेरिकी सीनेटर ने भारत में चुनाव को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से तैयारी के बारे में पूछा

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर ने 'मेटा' के मालिकाना हक वाले व्हाट्सऐप समेत सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा है कि उन्होंने भारत में चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां की हैं। सीनेटर माइकल बेनेट के मुताबिक, भारत में सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल कर फर्जी और झूठी सामग्री साझा करने का रिकॉर्ड रहा है। अमेरिकी चुनावों पर नज़र रखने वाली सीनेट की खुफिया और नियम समिति के सदस्य सीनेटर बेनेट ने सोशल मीडिया मंचों का संचालन करने वाली कंपनियों को भारत में चुनाव की घोषणा से पहले पत्र लिखकर उक्त जानकारी मांगी है।

बेनेट ने 'अल्फाबेट', 'मेटा' (फेसबुक), 'टिकटॉक', 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के अधिकारियों को पत्र लिखा है जिसमें इन कंपनियों से भारत समेत विभिन्न देशों में चुनाव को लेकर उनकी तैयारियों के बारे में पूछा गया है।

बेनेट ने पत्र में कहा, 'आपके मंचों से चुनावों में होने वाले खतरे नए नहीं हैं - पिछले चुनावों में उपयोगकर्ताओं ने 'डीपफेक' और डिजिटल रूप से छेड़छाड़ कर सामग्री को पोस्ट किया था - लेकिन अब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए जोखिम बढ़ाएगा।' उन्होंने कहा कि उन्नत एआई उपकरणों के माध्यम से अब कोई भी वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो का निर्माण कर सकता है जो चिंताजनक है। साल 2024 में 70 से ज्यादा देशों में चुनाव होने हैं और दो अरब से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साल 2024 'लोकतंत्र का वर्ष' है। इस साल ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, यूरोपीय संघ, फिनलैंड, घाना, आइसलैंड, भारत, लिथुआनिया, नामीबिया, मेक्सिको, मोल्दोवा, मंगोलिया, पनामा, रोमानिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका में चुनाव होने हैं।

'एक्स' के एलन मस्क, 'मेटा' के मार्क जुकरबर्ग, 'टिकटॉक के शो जी चू और अल्फाबेट के सुंदर पिचाई को लिखे पत्र में बेनेट ने इन मंचों की चुनाव संबंधी नीतियों, सामग्री नियंत्रण (मॉडरेशन) दल और एआई से बनाई गई सामग्री की पहचान करने के लिए अपनाए गए उपकरणों की जानकारी मांगी गई है। साथ में इसकी भी जानकारी मांगी गई है कि सामग्री नियंत्रण दल कितनी भाषाओं में हैं।

उन्होंने कहा, 'दुष्प्रचार और फर्जी सूचना तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को धुंधला करके लोकतांत्रिक चर्चा में जहर घोलते हैं। आपके मंचों को लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं करना चाहिए।'

सीनेटर ने कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रमुख सोशल मीडिया मंचों में 'मेटा' के स्वामित्व वाला व्हाट्सऐप भी शामिल है और इनका भ्रामक व झूठी सामग्री को बढ़ावा देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। राजनीतिक तत्व जो अपने लाभ के लिए जातीय आक्रोश को बढ़ावा देते हैं, उन्हें आपके मंचों पर दुष्प्रचार नेटवर्क तक आसान पहुंच मिल गई है।' इसके बाद बेनेट ने उनकी नई नीतियों और भारत चुनावों के लिए तैनात किए गए लोगों के विवरण के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि ÷आपने 2024 के भारतीय चुनाव की तैयारी को लेकर कोई नई नीतियां अपनाई हैं?

बेनेट ने पूछा, 'आपने असमी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथली और डोगरी में कितने सामग्री नियंत्रकों को फिलहाल तैनात किया हुआ है।' सीनेटर ने सोशल मीडिया कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से कहा कि उनके मंच एआई से बनी सामग्री को रोकने के साथ-साथ पारंपरिक फर्जी सामग्री को रोकने में भी नाकाम साबित हुए हैं। सीनेटर के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी खुफिया विभागों के प्रमुखों से सुना है कि रूसी, चीनी और ईरानी सरकारें अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकती हैं।

रूस में राष्ट्रपति चुनाव, वोटिंग के बीच हिंसा

-यूक्रेनी बॉर्डर से सटे शहर में आगजनी; कई पोलिंग बूथ में तोडफ़ोड़

मॉस्को (एजेंसी)। रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग के बीच आगजनी और हिंसा हो रही है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे बेलगोरोड शहर में पुतिन विरोधी लोगों ने कई जगह आग लगा दी। वहीं, राजधानी मॉस्को में लोगों ने कई पोलिंग बूथ में तोडफ़ोड़ की। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है।

रूस में 15 मार्च को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। पहली बार तीन दिन वोटिंग हो रही है। रूसी नागरिक जो किसी क्रिमिनल केस में जेल की सजा न काट रहा हो, वो 17 मार्च तक वोट कर सकते हैं। वहीं, नतीजे मॉस्को के समय के मुताबिक, 17 मार्च की रात तक जारी हो सकते हैं।

महिला ने पोलिंग बूथ में स्याही डाली

सेंट पीटर्सबर्ग में एक लड़की ने स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि 20 साल की एक लड़की ने पुतिन के खिलाफ विरोध जताने के लिए आग लगाई। उसे हिरासत में लिया गया है। वहीं, राजधानी मॉस्को में एक महिला ने बैलट बॉक्स में स्याही डाल दी। मॉस्को के अन्य पोलिंग बूथ को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने ऐसा करने वाली एक अन्य महिला को भी हिरासत में लिया। इधर, स्याही डालने वाली महिला को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में हिरासत में लिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को के अलावा वोरोनिश, कराचे-चर्केसिया और रोस्तोव शहर से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। साइबेरियाई क्षेत्र खांटी-मानसी में एक महिला ने बैलट बॉक्स जलाने की कोशिश की।

पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला। 14 मार्च को रूस के चुनाव आयोग ने कहा था- देश में 11.23 करोड़ मतदाता हैं। इन वो लोग भी शामिल हैं जो रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 19 लाख वोटर देश से बाहर रहते हैं। इस बार रूस में ऑनलाइन वोटिंग की भी सुविधा रहेगी। यह सुविधा रूस के 27 क्षेत्रों और क्रीमिया में होगी। क्रीमिया यूक्रेन का वही क्षेत्र है, जिस पर रूस ने साल 2014 में कब्जा कर लिया था।

इमरान खान की पार्टी सुन्नी इत्तेहाद परिषद के साथ विलय की योजना बना रही, चुनाव आयोग के फैसले पर दारोमदार

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शीर्ष नेता ने पार्टी की योजना का खुलासा किया कि अगर आयोग ने हाल के अंतर-पार्टी चुनावों को स्वीकार कर लिया और अपना प्रतिष्ठित चुनाव चिह्न वापस कर दिया तो वे सुन्नी इत्तेहाद कार्उंसिल (एसआईसी) के साथ विलय कर देंगे। पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन-न्यूज़टीवी के साथ एक साक्षात्कार में पीटीआई के असद क़ैसर ने कहा कि अगर पार्टी को हालिया संगठनात्मक चुनावों के बाद अपना चुनाव चिन्ह वापस मिल जाता है, तो दोनों पार्टियां विलय कर लेंगी और पीटीआई ही रहेंगी। एसआईसी पाकिस्तान में इस्लामी राजनीतिक और बरेलवी धार्मिक दलों का एक राजनीतिक गठबंधन है, जिसे 8 फरवरी के चुनावों में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त है।

क़ैसर ने पुष्टि की कि पीटीआई समर्थित उम्मीदवार जो एसआईसी में शामिल हुए हैं, वे गठबंधन के साथ बने रहेंगे और यदि चुनाव चिन्ह का मुद्दा हल हो जाता है तो इसमें विलय कर लेंगे।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल दिसंबर में कराए गए पिछले संगठनात्मक चुनावों को खारिज करने के बाद हुए ताजा इंट्रा-पार्टी चुनावों में बैरिस्टर गोहर अली खान को हाल ही में पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर इमरान खान द्वारा स्थापित पीटीआई को अपने अंतर-पार्टी चुनावों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हालिया चुनाव पिछले दो वर्षों में तीसरा प्रयास है। ईसीपी ने पहले जून 2022 में हुए चुनावों को अत्यधिक आपत्तिजनक बताते हुए रद्द कर दिया था। क़ैसर ने उल्लेख किया कि एसआईसी के साथ जुड़ने का निर्णय लेने से पहले पार्टी के भीतर व्यापक विचार-विमर्श हुआ और वे इस मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।

पाकिस्तान ने किया राम मंदिर का जिक्र, भारत ने इस्लामोफोबिया पर सुनाई खरी-खरी

-संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की हुई किरकिरी

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के द्वारा राम मंदिर का जिक्र करने पर जमकर क्लास लगा दी है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधी ने पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया को लेकर पाठ भी पढ़ दिया है। भारत के प्रतिनिधी ने पाकिस्तान से कहा कि केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख और हिंसा व भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इस दौरान जब पाकिस्तानी दूत ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर का जिक्र किया तब भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की।

शुक्रवार को 193 सदस्यीय महासभा ने पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय को मंजूरी दी। 115 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया और भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन तथा ब्रिटेन सहित 44 देश मतदान से दूर रहे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने यहूदी-विरोध, 'ईसाईफोबिया' और इस्लामोफोबिया (इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह) से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना जरूरी है कि इस तरह का 'फोबिया' (पूर्वाग्रह) अब्राहिमी धर्मों से परे भी फैला हुआ है। कंबोज ने कहा, इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह स्वीकार करना जरूरी है कि दुनियाभर में 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और तीन करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला सिख धर्म, सभी धार्मिक पूर्वाग्रह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति धार्मिक पूर्वाग्रह की व्यापकता को स्वीकार करें। इस दौरान पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह और नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का भी जिक्र किया।

पुतिन के लिए बुरी खबर: रूस की रुक सकती है युद्ध में ईरान की मदद

तहरान (एजेंसी)। रूस में चुनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परेशानी बढ़ गई है। जहां लगातार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में ईरान - रूस की मिसाइल, ड्रोन, हवाई बम भेज कर बड़ी मदद कर रहा था, अब उस पर रोक लगती दिखाई दे रही है। अब जी 7 समूह ने ईरान को चेतावनी दी है। जी 7 समूह ने ईरान को संदेश दिया है कि रूस को मिसाइल न भेजें अगर उसने ऐसा किया तो उसको सख्त परिणाम भुगतने होंगे। जी 7 देशों ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने करीबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रूस को भेजी तो उसको दंड का सामना करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच दो साल से चल रहे युद्ध में ईरान - रूस को मिसाइल भेज रहा है। जिस पर जी 7 देशों का गुस्सा फुटा है। जी 7 देशों ने कहा कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यूरोप जाने वाली ईरान की एयर फ्लाइट तक पर भी बैन लगा दिया जाएगा।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, जी7 ईरान की यूरोप में फ्लाइट पर बैन लगा देगा। बता दें, ईरान एयर यात्रियों को ईरान से यूरोप के कई शहरों तक ले जाती है। जी 7 इस उड़ान पर ही बैन लगा देंगे। अधिकारी ने कहा कि हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात की पुष्टि नहीं कर सका है कि मिसाइल पहले ही रूस को भेजी जा चुकी है या नहीं। ईरान पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों के बीच बातचीत का मुद्दा रहा है। जी7 के बयान में कहा गया है कि रूस को ईरानी मिसाइलें भेजना रूस को यूक्रेन पर हमला करने में मदद करेगा। ईरान द्वारा कुछ मिसाइलों, ड्रोनों और अन्य प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध अक्टूबर में समाप्त हो गए है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान को मिडिल ईस्ट और रूस में अपने प्रतिनिधियों को हथियारों के निर्यात पर साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध बरकरार रखा। क्योंकि ईरान की तरफ से भेजी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलें रूस के लिए यूक्रेन में युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए एक शक्तिशाली नया हथियार होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने पहले ही रूस को ड्रोन, निर्देशित हवाई बम और तोपखाना गोला-बारूद भेजा है।

संपादकीय

पारदर्शिता जरूरी

इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरे देश में चर्चा स्वाभाविक है और इसी कड़ी में देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों और सबसे बड़े सरकारी बैंक-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर मिली फटकार कोदेखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एसबीआई को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। वास्तव में, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जो सूची पोस्ट हुई है, उसे अधूरा माना जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, यह तो पता चल रहा है, लेकिन इससे किसे लाभ हुआ या उसका किस पार्टी ने लाभ लिया, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। कोई अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जो सूची के साथ शामिल नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद एसबीआई को अपनी सूची को और स्पष्ट करना होगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप पहले ही कार्रवाई करनी ही चाहिए थी, ताकि उस पर उंगली न उठती। इसमें कोई दोराय नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक चंदे के लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। यहां पारदर्शिता का सीधा अर्थ है कि लोगों को चंदे के बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए। किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं? जब एक बार पैसे के लेन-देन के बारे में साफ तौर पर पता चल जाता है, तब लोग यह आकलन करने की स्थिति में होते हैं कि पैसा क्यों लिया गया होगा या चंदा क्यों दिया गया होगा? दरअसल, चंदे की पूरी व्यवस्था ही विवेक पर निर्भर करती है। देने वाला अपने विवेक से देता है और जाहिर है, जो करोड़ों रुपये देगा, वह कुछ फायदे लेने के बारे में भी जरूर सोचेगा। आज के महंगे और पूंजीवादी दौर में यह सोचना बहुत भोलापन होगा, अगर हम यह सोचें कि अब तक करोड़ों रुपये का चंदा स्वेच्छा से लिया और दिया जाता रहा है। बहरहाल, जहां तक एसबीआई या किसी अन्य संस्था का सवाल है, तो हर हाल में पारदर्शिता के पक्ष को ही मजबूत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में किसी संस्था को जरूरी सूचना छिपाने का हक नहीं होना चाहिए। केवल देश की सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों की ही गोपनीयता सुनिश्चित रहनी चाहिए। बाकी तंत्र का कोई भी हिस्सा अगर किसी तरह का लेन-देन कर रहा है, तो इसके बारे में लोगों को पूरी सूचना होनी ही चाहिए। मतलब, एसबीआई को देश और उसके लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, अगर उसका व्यवहार कहीं से भी इस संदर्भ में उदासीन दिखे, तो चिंता होती है। पहले भी अनेक मौके आए हैं, जब हमने इस बैंक का पक्षपाती रवैया देखा है। शीर्ष अदालत की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया है कि एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है। अब एसबीआई को अपनी विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। यह ध्यान देने की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गहरी तफ्तीश के लिए अब एसआईटी के गठन की मांग हो रही है। इसका सीधा-सा मतलब है कि यह विवाद जल्दी नहीं सुलझने वाला। कुल मिलाकर, एसबीआई और अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं को सावधान हो जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला एक नजीर है। अब सबको कानून सम्मत पारदर्शिता के लिए काम करना होगा। एसबीआई पर देश को काफी भरोसा रहा है, उसकी साख को और चोट न पहुंचे, इसकी चिंता उसे ही करनी है।

प्रदीप छाजेड़
(बोरावड़)

आज का राशिफल

मेष — शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

वृषभ — पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

मिथुन — दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्त्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।

कर्क — पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।

सिंह — रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या — पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।

तुला — आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृश्चिक — पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु — जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।

मकर — दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ — गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन — पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं किसान

देविंदर शर्मा

कई दशक पहले, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक डॉ. एमएस रंधावा ने एक लेख में किसानों और खेती के बारे में लोकप्रिय धारणा के बारे में बात की थी। एक किसान निस्संदेह बहुत मेहनती होता है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश आती हो; आप हमेशा उसे खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों ने अपने श्रम से, पसीना बहाकर अकेले ही देश को भूख के जंजाल से बाहर निकाला है। लेकिन डॉ. रंधावा को उस समय समाज में प्रचलित एक किसान की स्वीकृत छवि से परेशानी हुई। आमजन की कल्पना में, किसान एक सादी पोशाक पहनता है, अक्सर एक मैला कुर्ता व धोती पहनता है और टूटी-टांके लगी धूल-धूसरित जूती पहनकर चलता है। उम्मीद रहती है कि आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करता है, और जब भी आप उसे दोपहिया वाहन चलाते हुए देखते हैं, तो अक्सर भौंहें तन जाती हैं। हालांकि अब वक्त बदल गया है लेकिन किसान और खेती के बारे में धारणा अब भी पूर्ववत ही कायम है। साइकिल की जगह भले ही दोपहिया वाहन ले चुका है, जिसे अब कार द्वारा बदला जा चुका है, ऊपरी तबके में किसानों के पास कई बार शानदार मॉडल भी होते हैं, लेकिन एक पेशे के रूप में खेती के बारे में आमजन की सोच में बहुत बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण-शहरी विभाजन का प्रतिबिंब, खेती अभी भी शहरी हाशिये पर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर, यदि कोई किसान शहरी दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे अभी भी नापसंद किया जाता है, और यहां तक कि खान-पान के तौर-तरीके अपनाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर पिज्जा खाना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐसे समय में जब एक घरेलू सहायिका को अपने कार्यस्थल तक जाने को स्कूटी चलाते हुए देखना असामान्य नहीं है, एक किसान द्वारा ट्रैक्टर पर महंगे म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करना मंजूर नहीं है। असल में, खेती एक दोयम दर्जा शब्द बन गया है। किसानों के प्रति इतनी गहरी उदासीनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर सवाल उठाने वाले प्रबल वृत्तांत के साथ ही तिरस्कार और अवमानना का भाव भी सामने आता है। विरोध कर रहे किसानों पर लगातार अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं और मुख्यधारा के माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कृषक समुदाय के खिलाफ व्याप्त कुंठा के भावों का प्रतिबिंब हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि किसान बहुत पाला-पोसा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी व मुफ्त बिजली मिलती है, और वे इनकम टैक्स नहीं देते। किसानों की आय में कोई भी वृद्धि उपभोक्ता कीमतों पर असर डालेगी। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसलिए किसानों को बढ़ी हुई आय के अधिकार से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चारों ओर इतनी गलत सूचनाएं, और त्रुटिपूर्ण आर्थिक तर्क उछाले जा रहे हैं कि मिथक व वास्तविकता में भेद करना आसान नहीं। किसी भी मामले में, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री और मीडिया फैलाए जा चुके भ्रम से खुश लगते हैं। चाहे वह काल्पनिक खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े हों या राष्ट्रीय खजाने पर संभावित वित्तीय बोझ, सभी प्रकार के संदिग्ध आंकड़े प्रचलित हैं। मूल मान्यता यह है कि किसानों की आय में कोई भी बढ़ोतरी बाजार को बिगाड़ देगी और इससे व्यापार और उद्योग के मुनाफे में कमी आएगी। हकीकत में, जो स्वाभाविक से भी ज्यादा हो चुका है वह ये कि किसान को निरंतर गरीबी में रखने को लेकर देश संतुष्ट नजर आता है। यदि किसान इतने लाड़ले होते तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि औसत कृषि आय निम्नतम स्तर पर बनी रहनी चाहिये थी। जो पहले कहा जा चुका है उसे दोहराने के जोखिम पर, कृषि परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण 2021 की नवीनतम रिपोर्ट की गणना के मुताबिक, कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। इससे यह भी पता चला कि खेती से होने वाली आय मनरेगा श्रमिकों की मासिक मजदूरी से भी कम थी। इससे भी बुरी बात, किसानों की स्थिति पर देश के एक अंग्रेजी दैनिक में बीती 23 फरवरी को प्रकाशित विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में औसत कृषि आय अभी भी कम है और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, जहां 90 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं, आय बहुत कम है। एक अध्ययन में यह पता चला है कि आंध्र प्रदेश के कई सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 14 प्रतिशत पारिवारिक आय सरकारी योजनाओं से आती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय मदद शामिल है। इसके अलावा, जैसा कि कुछ दिन पूर्व पेश 2022-23 घरेलू खर्च सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक पेशेगत उद्यम के रूप में खेती कितनी अनिश्चित हो गई है, जिसमें कृषि परिवारों का खर्च ग्रामीण परिवारों से कम हो गया है। आय कम होने के कारण उपभोग कम है। इसलिए यह कहना कि किसान आयकर नहीं देते, उचित नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम सबसे पहले किसानों को कर योग्य आय दें? किसी भी स्थिति में, यह उपभोक्ता केंद्रित नजरिया ही है जो असल में किसान को सही कीमत प्रदान करने से इनकार करता है। एक-दो साल को छोड़ दें तो व्यापार की शर्तें नकारात्मक रही हैं। कई अध्ययनों में सामने आया कि एक दशक से ज्यादा वक्त से ग्रामीण मजदूरी स्थिर है या फिर घट रही है। कृषक परिवारों के उपभोग स्तर में गिरावट भी यह इंगित करती है। और फिर भी, जैसे ही उच्चतर एमएसपी घोषित किया जाता है, अखबारों के संपादकीय लगभग हर बार इसे खाद्य मुद्रास्फीति में प्रत्याशित बढ़ोतरी से जोड़ने लगते हैं। दरअसल, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना करने के बाद उनकी कीमतों की घोषणा की जाती है, तो वह उनकी कीमतों की सिफारिश करने से पहले इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता और बाजार कीमतों के रुझान पर गौर करता है। इसके अलावा, खाद्य मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जायज सीमा के भीतर रखने से, लोगों को अक्सर यह अहसास नहीं होता है कि किसान वास्तव में उपभोक्ताओं और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के हालिया अध्ययन बताता है कि भारतीय किसान साल 2000 से घाटे की खेती कर रहे हैं, जिस वर्ष इसने उत्पादक-सब्सिडी मदद का आकलन करना शुरू किया था। किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह मार्केट में किसानों को मिलने वाली कीमत और सब्सिडी, कुछ राज्यों में फ्री बिजली मदद भी, को जोड़ने के बाद हुआ है।

ओईसीडी डेटा यह भरपूर स्पष्ट करता है कि बाजार को कायम रखने के लिए, हमने जान-बूझकर खेती को कंगाल बनाए रखा है। जब तक हम किसान को मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना जारी रखेंगे, तब तक डॉ. एमएस रंधावा द्वारा उकेरी गयी किसान की छवि बदलने वाली नहीं है। किसान को संकट से उबारने के लिए एमएसपी की गारंटी पहला कदम होगा, लेकिन उसे दशकों से हो रहे घाटे की पूर्ति करने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जब तक किसानों और समाज के अन्य वर्गों के बीच आय में बराबरी यकीनी बनाने के प्रयास नहीं किये जाते तब तक किसान अपनी छवि से बाहर नहीं निकल सकता है।

लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

भाजपा को भारी पड़ सकता है अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटना!

(लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन)

भाजपा ने उत्तराखंड में हरिद्वार से मौजूदा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक व गढ़वाल से मौजूदा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर सबको हैरत में डाल दिया है।निशंक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार क्षेत्र में कभी सक्रिय नही रहे ,को टिकट देना भाजपा को भारी पड़ सकता है।हालांकि हरिद्वार सीट पर कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नही खोले है,लेकिन यदि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत या फिर जैसा कि चर्चा चल रही है निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ते है तो दोनो ही स्तिथियों में भाजपा के लिए कड़ी टक्कर होगी।जहां तक गढ़वाल सीट का सवाल है वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के बीच इस कदर कांटे की टक्कर रहेगी कि हार जीत के दावे करना मुश्किल है।कांग्रेस ने अल्मोड़ा सीट पर एक बार फिर भाजपा के अजय टम्टा के सामने प्रदीप टम्टा पर दांव खेला है। भाजपा ने अपने सीटिंग सांसद अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं सन 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप टम्टा को एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदीप टम्टा राज्य बनने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में 2002 से सोमेश्वर सीट से विधायक भी रहे है,साथ ही वे अल्मोड़ा से 15वी लोकसभा के कांग्रेस सांसद रहे है, इसके बाद सन 2016 में उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था।

पौड़ी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे है,को अपना प्रत्याशी बनाया है। गणेश गोदियाल सन 2002 में कांग्रेस के टिकट पर थली सेंड से और सन 2012 में श्रीनगर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचें थे। इसके साथ-साथ पार्टी हाईकमान ने गणेश गोदियाल को जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक प्रदेश कांग्रेस के मुखिया की जिम्मेदारी भी दी थी। इसीलिए भाजपा ने पौड़ी सीट पर राज्यसभा सांसद व पार्टी प्रवक्ता रहे अनिल बलूनी को उनके सामने चुनाव मैदान में उतारा हैं। गढ़वाल से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला कांग्रेस के उम्मीदवार है, जहां भाजपा ने अपनी सीटिंग सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पर एक बार फिर भरोसा जताया है । कांग्रेस ने जोत सिंह गुंसोला को टिकट देकर उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा का ईनाम दिया है। जोत सिंह गुंसोला वर्ष1988 और वर्ष 1997 दो बार मसूरी पालिका परिषद के चेयरमैन रहे है, वहीं कांग्रेस की तरफ से 2002 से 2012 तक दो बार मसूरी विधानसभा से विधायक भी रहे है। गुंसोला वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पद पर विराजमान है।उत्तराखंड में हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी।दोनों पार्टियां राज्य की जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सत्तारूढ़ सरकार ने 2014 और 2019 दोनों मेगा चुनावों में सभी 5 लोकसभा सीटें जीतीं थी। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि राज्य की जनता को उनकी पार्टी पर पूरा भरोसा है।वही कांग्रेस ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में वापसी की दिशा में कई छोटे कदम उठाए, जिसने 18वीं लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों के लिए परीक्षण का मैदान बना दिया है। बीजेपी अभी भी राज्य और केंद्र दोनों में मजबूत स्थिति का दावा कर रही है।उत्तराखंड राज्य में आम चुनाव की चुनाव अवधि पहली तिमाही की होती हैं। हर बार की तरह देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए लोकसभा चुनाव कार्यक्रम अप्रैल के महीने में मिल सकता है।छोटा राज्य होने के कारण उत्तराखंड के खाते में बहुत कम संख्या में लोकसभा सीटें हैं, इसलिए राज्य में आम चुनाव एक ही चरण में कराए जाते हैं।2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार में ही चुनाव कराने का परिदृश्य होगा,उत्तराखंड एक ही चरण में मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। उत्तराखंड में लोकसभा की पांच सीटो में से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए अल्मोड़ा आरक्षित है। बीजेपी ने 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में सभी पांच सीटें जीती थीं। कांग्रेस अपने नवगठित इंडिया गठबंधन की मदद से आगामी मेगा चुनावों में अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करेगी,वही भाजपा फिर से पांचों सीटे जीतने का दावा कर रही है।

लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस भले ही प्रदेश की पांचों लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हो,लेकिन धरातल पर अभी भी नेताओं के बीच एकता का अभाव है।वही प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय नेता चुनाव लड़ने से जहां बचते नजर आ रहे हैं वही लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से हारने के बाद इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। ऐसे में इस चुनाव के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के वजूद की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फ़िलहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई है, ताकि प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर काबिज हो सके ।चुनावी तैयारी के बीच उत्तराखंड की राजनीति में इन दोनों उथल पुथल भी देखा जा रहा है, एक तरफ भाजपा ने पांचों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी, शैलेंद्र रावत और अशोक वर्मा जैसे कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस अभी भी हरिद्वार व गढ़वाल लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। कांग्रेस आलाकमान को प्रत्याशियों के चयन में काफी समय लगना कांग्रेसियों की बेचैनी बढ़ा रहा है।नेताओं द्वारा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करने की एक वजह चुनाव का मंहगा होना भी है। मौजूदा समय में एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, साथ ही प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को भी एक चुनोती के रूप में देखा जा रहा है।वही भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी आर्थिक रूप से इतने समर्थ हो गए हैं कि वो अपने बलबूते चुनाव लड़ सकते हैं। सीटिंग पार्टी को आसानी से चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी मिल जाता है, जबकि विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा एकत्र करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।राजनीतिक समीकरणों के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपनी फिक्र करें,कांग्रेस की फिक्र न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाते-बनाते भाजपा ने खुद को कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया है, वर्तमान समय में आज 9 में से 5 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पृष्ठिभूमि से हैं, ऐसे में भाजपा किसी को कांग्रेस से आयात करके मुख्यमंत्री भी बना दे, जो ज्यादा बेहतर होगा।जिसका प्रतिकूल प्रभाव भाजपा के इस लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा,क्योंकि दलबदलुओं के कारण निष्ठवान भाजपाई भी उपेक्षित है।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक वरिष्ठ पत्रकार है)

कानून बनाने से नहीं होता, समस्याओं और अपराधों पर नियंत्रण

(लेखक-सनत जैन)

अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में भी बड़े जोर शोर के साथ मनाया गया।उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।उन्हें समय पर न्याय मिले। उपभोक्ता अधिकारों को लेकर कानून भारत में भी प्रचलित है। इस कानून के तहत 90 दिन के अंदर फोरम के लिए शिकायत का निराकरण करना आवश्यक होता है। जिला उपभोक्ता फोरम, स्टेट फोरम और राष्ट्रीय फोरम पर उपभोक्ताओं के मामले सुने जाते हैं। विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं और कंपनी और तथा सेवा देने वालों के विवाद का निराकरण होता है। कानून में प्रावधान होने के बाद भी जिला उपभोक्ता अदालतों में कई वर्षों तक मामले लटके रहते हैं। राज्य सरकारों द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है। जिसके कारण जिला उपभोक्ता अदालतों में हजारों की संख्या में शिकायतें, कई महीने और वर्षों तक पेंडिंग बनी रहती हैं। उनकी वर्षों सुनवाई ही नहीं हो पाती है। उपभोक्ता फोरम के चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में 30528 शिकायतें जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित है। चूंकि समय पर न्याय नहीं मिलता है। छोटे-मोटे मामलों में लोग शिकायत ही नहीं कर रहे हैं। राज्य उपभोक्ता फोरम में लगभग 10001 मामले भोपाल, इंदौर और जबलपुर बेंच में लंबित है। इसमें कई मामले 10 साल से अधिक से आयोग में लंबित हैं। राज्य उपभोक्ता फोरम में मुश्किल से दो या तीन मामलों की ही सुनवाई हो पाती है। बाकी के प्रकरणो मैं तारीख देकर आगे बढ़ा दिया जाता है।लगभग सभी प्रदेशों में उपभोक्ता फोरम की यही हाल है। जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकारें सजग नहीं होती है।महीनों और वर्षों तक फोरम के पद खाली पड़े रहते हैं। उपभोक्ता फोरम में 90 दिन के अंदर शिकायतों पर फैसला करना होता है। फोरम मे 90 दिन में सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाती है। इस तरह के कानून से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा है। उल्टे फोरम के चक्कर लगाते-लगाते उपभोक्ता न्याय पाने की आशा ही छोड़ देता है। भारत में कानून बनाने में सरकार, चाहे वह केंद्र की हो, या राज्य की सरकार हो। सरकारें कानून बड़ी तेजी के साथ बनाती है।उसके नियम निश्चित रूप से नागरिकों के हितों मे बने होते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था और कानून के बारे में बात करें, न्यायालयों से कई वर्षों तक नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता है। जिसके कारण अब लोग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख से परेशान होकर, न्याय व्यवस्था से परेशान हैं। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार ने काफी कड़े कानून बनाए। कानून बन जाने के बाद ऐसा लग रहा था, कि अब यौन उत्पीड़न के अपराध कम होंगे। जब से कड़े कानून बनाए गए हैं।उसके बाद अपराधों की संख्या घटने के स्थान पर निरंतर बढ़ती जा रही है। कड़े कानून बन जाने के बाद, अब अपराधी यौन अपराध के साथ-साथ अपराध छुपाने के लिए हत्या जैसे अपराध भी करने लगे हैं।खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने नियम और कानून बनाए हैं। खाद्य पदार्थों की मिलावट तो कम नहीं हुई। मिलावट की जांच के नाम पर सरकारी तंत्र ने अपनी वसूली जरूर तेज कर दी। महीनों और सालों तक मिलावट के शक में जो सैंपल एकत्रित किए जाते हैं। उनकी जांच ही नहीं हो पाती है। मामले न्यायालयों में पेश किए जाते हैं। जहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियां जुर्माना देकर बच जाती हैं। गरीब गुरबों को जरूर जेल जाना पड़ता है। खाद्य पदार्थों का असंगठित क्षेत्र का रोजगार पूरी तरह से खत्म हो रहा है। वहीं कॉर्पोरेट का व्यवसाय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में अमूल दूध और मदर डेयरी के दूध के सैंपल की जांच हुई। दोनों कंपनियों के दूध में मिलावट पाई गई। गाजियाबाद के एसडीएम ने जुर्माना करके उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया। दिल्ली की एक कोर्ट में मदर डेयरी के दूध में मिलावट होने के आरोप में जुर्माना करके छोड़ दिया। खाद्य पदार्थों में मिलावट और उपभोक्ताओं के साथ फर्जी विज्ञापन बड़े-बड़े फर्जी दावे करके लोगों को चूना लगाया जाता है।कानून बने हुए हैं।

निश्चित समय सीमा पर फैसला करने का प्रावधान होता है।इसके बाद भी नागरिकों को, चाहे वह उपभोक्ता के रूप में हो, अथवा न्याय पाने की आशा से न्यायालय तक खुद चलकर पहुंचा हो।उसे समय पर न्याय नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार और सामाजिक संगठनों को गंभीरता से विचार करना होगा। कानून बनाने से अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

राजकुमारी और चांद खिलौना

एक राजा था उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। क्योंकि उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? तुम्हारे इलाज के लिउ कुछ भी करने को तैयार हूं।

यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली फिर मेरे लिए चांद मंगवा दिजीए। मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबियत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूं।

राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया और उससे धीरे से कहा रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए।

चांद प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला महाराज मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगवा सकता हूं लेकिन चांद लाना मुश्किल है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरन्त दरबार से बाहर जाने का आदेश दे दिया। और प्रधान सेनापति को बुलवाया।

प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उनसे भी चांद लाने की बात कही सेनापति ने भी चांद लाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और तर्क दिया कि चांद को कोई भी नहीं ला सकता। वह यहां से डेढ़ लाख मील दूर है।

राजा ने उसे भी चले जाने को कहा और अपने खजांची को बुलाया उसने भी राजकुमारी के लिए चांद लाने में असमर्थता जताई। जाओ यहां से जाओं राजा चीखा और बोला दरबारी जोकर को बुलाओ। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा सरकार आपने मुझे बुलाया? हां राजा रो पड़ा जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उनकी तबियत ठीक नहीं होगी क्या तुम चांद ला सकते हो?

हां क्यो नहीं पर राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है कोई बात नहीं मैं खुद उनसे जा कर पूछ लेता हूं। जोकर बोला और सीधे राजकुमारी में कमरे में चला गया। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा कि चांद लाए। जोकर ने कहा अभी नहीं लेकिन जल्द ला दूंगा। पहले ये बताओं कितना बड़ा चांद चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि मेरे अंगूठे के नाखून बराबर क्योंकि जब मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूं तो वह दिखाई नहीं देता।

अच्छा यह और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है राजकुमारी ने बोला।

ठीक है आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। जोकर ने कहा और राजा के पास चला गया और उसने राजा को बोला कि मैं कल राजकुमारी के लिए चांद का खिलौना ले आऊंगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवा कर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबियत ठीक हो गई। लेकिन राजा को चिन्ता खाय जा रही थी कि जब राजकुमारी जब खिड़की में से चांद को देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी कि पिताजी ने उससे झूठा वादा किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा कि अच्छा राजकुमारी ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो आसमान में कैसे निकल आया?

राजकुमारी हंस कर बोली तुम मूर्ख हो जैसे मेरा जब दंत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है वैसे ही चांद भी दूसरा निकल आया है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के साथ खिलौने से खेलने लगा।

गुरु नानकदेव की सीख

एक डाकू गुरु नानकदेवजी के पास आया और चरणों में माथा टेकते हुए बोला- मैं डाकू हूँ, अपने जीवन से तंग हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए। नानकदेवजी ने कहा- तुम आज से चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। डाकू प्रणाम करके चला गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और कहने लगा- मैंने झूठ बोलने और चोरी से मुक्त होने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु मुझसे ऐसा न हो सका। मैं चाहकर बदल नहीं सका। आप मुझे उपाय अवश्य बताइए।

गुरुनानक सोचने लगे कि इस डाकू को सुधरने का क्या उपाय बताया जाए। उन्होंने अंत में कहा- जो तुम्हारे मन में जो आए करो, लेकिन दिन भर झूठ बोलने, चोरी करने और डाका डालने के बाद शाम को लोगों के सामने किए हुए कामों का बखान कर दो। डाकू को यह उपाय सरल जान पड़ा।

इस बार डाकू पलटकर नानकदेवजी के पास नहीं आया क्योंकि जब वह दिनभर चोरी आदि करता और शाम को जिसके घर से चोरी की है उसकी चौखट पर यह सोचकर पहुँचता कि नानकदेवजी ने जो कहा था कि तुम अपने दिन भर के कर्म का बखान करके आना लेकिन वह अपने बुरे कामों के बारे में बताते में बहुत संकोच करता और आत्मग्लानि से पानी-पानी हो जाता। वह बहुत हिम्मत करता कि मैं सारे काम बता दूँ लेकिन वह नहीं बता पाता।

हताश-निराश मुँह लटकाए वह डाकू एक दिन अचानक नानकदेवजी के सामने आया। अब तक न आने का कारण बताते हुए उसने कहा-मैंने तो उस उपाय को बहुत सरल समझा था, लेकिन वह तो बहुत कठिन निकला। लोगों के सामने अपनी बुराइयाँ कहने में लज्जा आती है, अतः मैंने बुरे काम करना ही छोड़ दिया। इस तरह नानकदेव जी ने उसे अपराधी से अच्छा इंसान बना दिया।

शेख चिल्ली की चिट्ठी

बच्चो, तुमने मियाँ शेख चिल्ली का नाम सुना होगा। वही शेख चिल्ली जो अकल के पीछे लाठी लिए घूमते थे। उन्हीं का एक और कारनामा तुम्हें सुनाएँ।

मियाँ शेख चिल्ली के भाई दूर किसी शहर में बसते थे। किसी ने शेख चिल्ली को बीमार होने की खबर दी तो उनकी खैरियत जानने के लिए शेख ने उन्हें खत लिखा। उस जमाने में डाकघर तो थे नहीं, लोग चिट्ठियाँ गाँव के नाई के जरिये भिजवाया करते थे या कोई और नौकर चिट्ठी लेकर जाता था।

लेकिन उन दिनों नाई उन्हें बीमार मिला। फसल कटाई का मौसम होने से कोई नौकर या मजदूर भी खाली नहीं था अतः मियाँ जी ने तय किया कि वह खुद ही चिट्ठी पहुँचाने जाएँगे। अगले दिन वह सुबह-सुबह चिट्ठी लेकर घर से निकल पड़े। दोपहर तक वह अपने भाई के घर पहुँचे और उन्हें चिट्ठी पकड़ाकर लौटने लगे।

उनके भाई ने हैरानी से पूछा - अरे! चिल्ली भाई! यह खत कैसा है? और तुम वापिस क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई नाराजगी है?

भाई ने यह कहते हुए चिल्ली को गले से लगाना चाहा। पीछे हटते हुए चिल्ली बोले - भाई जान, ऐसा है कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी ले जाने को नाई नहीं मिला तो उसकी बजाय मुझे ही चिट्ठी देने आना पड़ा।

भाई ने कहा - जब तुम आ ही गए हो तो दो-चार दिन ठहरो। शेख चिल्ली ने मुँह बनाते हुए कहा - आप भी अजीब इंसान हैं। समझते नहीं। यह समझिए कि मैं तो सिर्फ नाई का फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे आना होता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता?

कैसे बनी आइसक्रीम

बच्चो हम सब आइसक्रीम तो खाते है पर कभी ये जानने की कोशिश पहले कैसे बनाया जाता था ? भारत में मुगल शासनकाल के दौरान आइस जाता है कि अरब जगत के लोगों ने सबसे पहले आइसक्रीम के उत्पादन में शुरूकिया। वे फलों की बजाय चीनी मिलाकर इसको मीठा करते थे। फालूद और अफगानिस्तान से मानी जाती है। करीब 200 ईसा पूर्व के आस-पा मिश्रण को जमाकर खाने की परंपरा मिलती है। रोम का शासक नीरो (37-6 को मंगाता था और उनमें फलों के ऊपरी हिस्से को मिलाकर खाता था।

18वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका की रेसिपी में आइसक्रीम बनाने की आधु ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार 1744 में पहली बार आइसक्रीम शब्द का उल्लेख मिलता है।दुनिया के पहले आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत 1776 में अमेरिका में हुई थी।20वीं सदी में ब्रिटेन में आइसक्रीम बनाने के आसान तरीके विकसित होने से बढोतरी हुई। उसी दौर में रेफ्रिजरेटर के अस्तित्व में आने के बाद इसको घरों में संरक्षित रखा जाना शुरूहुआ। साइकिल में लेकर इसे बेचने की शुरुआत लंदन में 1923 में हुई थी। जिसमें बेचने वाले डिब्बे पर लिखा होता था- स्टॉप मी ऐंड बाई वन। अमेरिका आइसक्रीम का दुनिया में सबसे बडा उपभोक्ता है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है।

बायजू की 53 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम फ्रीज

नई दिल्ली । अमेरिकी कोर्ट ने एडटेक कंपनी बायजू की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न कंपनी के 53.3 करोड़ डॉलर फ्रीज कर दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह पैसा कहीं उपयोग नहीं किया जा सकता। इस फैसले को कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्जदाताओं की जीत माना जा रहा है। उनकी मांग थी कि इस पैसे का उपयोग सिर्फ उन्हें भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए। थिंक एंड लर्न ने कानूनी विवादों में फंसने के बाद इस 53.3 करोड़ डॉलर को कथित तौर पर मॉर्टन हेज फंड में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद इसे एक अनाम ऑफ शोर ट्रस्ट में भेज दिया दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्जदाताओं ने मांग की थी कि टेक फर्म द्वारा इस पैसे के उपयोग को रोकने के लिए इसे कोर्ट में जमा करवा दिया जाए। कोर्ट ने बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन के भाई और कंपनी के डायरेक्टर रिजू रविंद्रन को निशाना बनाते हुए कहा कि आप बताइए पैसा कहां है। जज ने कहा, मैं उनका विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें पैसे की लोकेशन पता नहीं है। थिंक एंड लर्न उन्हें यह जानकारी क्यों नहीं दे रही कि पैसा कहां है। रवींद्रन के वकील ने तर्क दिया कि थिंक एंड लर्न में चल रहे संकट के लिए कर्जदाता ही जिम्मेदार हैं। यही लोग हमारे ऊपर लोन डिफॉल्ट का जरूरत से ज्यादा दबाव बना रहे थे। कंपनी डेलवेयर और न्यूयॉर्क की अदालतों में कर्जदाताओं से केस लड़ रही है।

जी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष नितिन मित्तल का इस्तीफा

नई दिल्ली । जी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष और समूह के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीओओ) नितिन मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने मित्तल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो पिछले दो साल से इस पद पर कार्यरत थे। जी एंटरटेनमेंट ने एक बयान में कहा कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनीत गोयनका द्वारा किये जाने वाले प्रौद्योगिकी और डेटा क्षेत्र में रणनीतिक बदलावों के बीच यह घोषणा की गई है। मित्तल ने कंपनी के कार्यक्षेत्र को सुव्यवस्थित करने की कवायद के बीच इस्तीफा दिया है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने उम्मीदवारों को किया शॉर्ट-लिस्ट

- 7000 से अधिक उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर भेजे

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए 7000 से अधिक उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर एसएमएस के माध्यम से भेजे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एचकेआरएन में विभिन प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है, यह सरासर गलत है। मुख्यमंत्री ने साथ ही आम लोगों से यह भी आग्रह किया कि एचकेआरएनएल में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आएं, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनमें लेवल-1 से लेवल-3 तक के पद शामिल हैं। इन पदों में विभिन्न अध्यापकों के 4216, चपरासियो के 650, सफाई कर्मचारियों के 787, चौकीदार के 466, पटवारियों के 226, ड्राइवरों के 52, शिफ्ट अटेंडेंट के 50, स्टाफ नर्स के 14, लीगल असिस्टेंट के 22, सहायक लाइनमैन के 24 पद सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं।

नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू, एसएचजी को खेती के लिए मिलेगा ड्रोन

नई दिल्ली ।

केन्द्र सरकार ने महिला किसानों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इसके तहत एसएचजी को ड्रोन दिया जाएगा। जिसका इस्तेमाल वो खेती में कर सकेंगी, जो आय बढ़ाने में सहायक होगा। मौजूदा समय में देशभर में करीब 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी का हिस्सा हैं। इस योजना के तहत देशभर के 14500 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को ड्रोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें मोदी सरकार 80 फीसदी सब्सिडी देगी। बचे हुए बीच 20 फीसदी पर लोन दिया जाएगा। इस लोन में भी एक और फायदा है। ब्याज में 3 फीसदी की छूट अलग से दी जाएगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार एक ड्रोन पैकेज की संभावित कीमत 10 लाख रुपये के करीब होगी और 10 लाख के ड्रोन में एसएचजी को आठ लाख की सब्सिडी मिलेगी। उसे केवल दो लाख चुकाना होगा और दो लाख का रुपये का लोन किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को ड्रोन पायलट को डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के लिए एक और महिला को को-पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह 15 दिन की ट्रेनिंग इसी पैकेज में शामिल होगी। इस योजना

के तहत ड्रोन का इस्तेमाल नैनो फर्टिलाइजर और कीटनाशक के छिड़काव में इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना को लागू करने में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की मदद ली जाएगी।

तांबे की कीमत 11 महीने के उच्चतम स्तर पर

मुंबई । चीनी स्मेल्टरों द्वारा उत्पादन में कटौती पर सहमति के बाद तांबे की कीमत 11 महीने के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लंदन मेटल एक्सचेंज पर तीन महीने का तांबा वायदा 1.5 फीसदी बढ़ गया और अप्रैल 2023 के बाद पहली बार 9,000 डॉलर प्रति टन के स्तर को पार कर गया। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में मई में डिलीवरी वाले तांबे की कीमत बढ़कर 4.06 डॉलर प्रति पाउंड (8,932 प्रति टन) पर पहुंच गईं। शंघाई वायदा एक्सचेंज में तांबा दो साल के उच्चतम स्तर 70,460 युआन प्रति टन पर पहुंच गया। गौरतलब है कि हाल ही में चीनी तांबा स्मेल्टरों द्वारा कीमतें बढ़ाने के प्रयास में कटौती करने पर समझौता हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि अभी तांबें की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, ये जून 2024 तक 9,500 डॉलर प्रति पर जा सकती है।

वर्ष 2030 तक रियल एस्टेट बाजार एक लाख करोड़ डॉलर का होगा: पुरी

नई दिल्ली । केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर के अनुमानित बाजार के साथ परिपक्व और विकसित रियल एस्टेट क्षेत्र होना चा हिए। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई की युवा शाखा द्वारा

आयोजित एक कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि रियल एस्टेट नियामक कानून रेरा का लागू होना पूरे क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी घटनाक्रम रहा है। पुरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत को आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक परिपक्व और विकसित रियल एस्टेट क्षेत्र की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर और वेयरहाउसिंग सहित वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश आ रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) की शुरुआत से भी रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। पुरी ने कहा कि रेरा एक परिवर्तनकारी घटना थी। अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक के पास लगभग 70 वर्षों तक कोई नियामक नहीं होना आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि देश भर में 1,22,553 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 86,262 रियल एस्टेट एजेंट इस नियामक के साथ पंजीकृत हैं।

सेंसेक्स और निफ्टी में आधा फीसदी की गिरावट रही

मुंबई ।

वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और विदेशी निवेशकों की लिवाली के दबाव में बीते सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को गिरावट और मंगलवार को हल्की बढ़त पर कारोबार हुआ। बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों पर नजर डालें तो अमेरिका में मुद्रास्फीति आंकड़े आने से पहले एशियाई प्रतिस्पर्धियों की सुस्त शुरुआत के बाद, भारतीय इक्विटी सूचकांक भी सोमवार को मामूली गिरावट के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स 95 अंक की गिरावट के साथ 74,024 पर खुला और 617 अंकों की गिरावट के साथ 73,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी50 14 अंक की गिरावट के साथ 22,479 पर खुला और 161 अंक फिसलकर 22,332 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 332.79 अंकों की बढ़त के साथ 73,831.88 के स्तर पर खुला और 165.32 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 61.25 अंक मजबूत होकर 22,393.90 पर खुला और 3.05 अंक चढ़कर 22,335.70 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 182.11 अंकों की बढ़त के साथ 73,877.85 के स्तर पर खुला और 906.07 अंकों की गिरावट के साथ 72,761.89 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 40.10 अंक मजबूत होकर 22,375 पर खुला और 338.00 अंक फिसलकर

21,997.70 पर बंद हुआ। पिछले सत्र में मुनाफावसूली के बाद गुरुवार को भारतीय इक्विटी सूचकांक लगातार दूसरे कारोबारी सत्र लाल निशान में खुले। बीएसई सेंसेक्स 252 अंक की गिरावट के साथ 72,509 पर खुला और 335.39 अंकों की बढ़त के साथ 73,097.28 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक की गिरावट के साथ 21,930 पर खुला और 148.96 अंकों की बढ़त के साथ 22,146.65 पर बंद हुआ। शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 416 अंकों की गिरावट के साथ 72,681 खुला और 453.85 (0.62 फीसदी) अंकों की गिरावट के साथ 72,643.43 पर बंद हुआ। निफ्टी 136 अंकों की गिरावट के साथ 22,010 पर खुला और 123.31 (0.56 फीसदी) अंक टूटकर 22,023.35 के स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.47 अरब डॉलर बढ़ा

नई दिल्ली ।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार आठ मार्च को समाप्त सप्ताह में 10.47 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 636.095 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.55 अरब डॉलर बढ़कर 625.626 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर, 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था लेकिन वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए पूंजी भंडार का उपयोग किया, जिससे मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक आठ मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 8.121 अरब डॉलर बढ़कर 562.352 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में उल्लिखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 2.299 अरब डॉलर बढ़कर 50.716 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार

(एसडीआर) 3.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.211 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा भी 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.817 अरब डॉलर हो गई।

एआई से वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ीं: दास

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से साइबर सुरक्षा चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय संस्थानों से ग्राहक जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा। दास ने हाल ही में यहां आरबीआई लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि विनियमित संस्थाएं वित्तीय लेनदेन, ग्राहक संपर्क और परिचालन गतिविधियों से जुड़े आंकड़ें अपने पास रखती हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के इस व्यापक भंडार में डेटा विश्लेषण के जरिए ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने का एक अनूठा अवसर निहित है। दास ने कहा कि डेटा विश्लेषण की ताकत का उपयोग करके विनियमित संस्थाएं ग्राहकों की जरूरतों का अच्छी तरह से अनुमान लगा सकती हैं, मुद्दों का तुरंत समाधान कर सकती हैं और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन बढ़ने के साथ निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। दास ने कहा कि एआई के आने के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती हैं।

एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने तीन क्रांतिकारी डेयरी सोल्यूशन्स लॉन्च किए

-अहमदाबाद स्थित कंपनी ने भारत का पहला एफटीआईआर-आधारित दूध विश्लेषक, गैस क्रोमैटोग्राफी मशीन और सोमैटिक सेल विश्लेषक लॉन्च किया -

अहमदाबाद ।

डेयरी और खाद्य परीक्षण सोल्यूशन्स में इनोवेशन के लिए विख्यात कंपनी एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने तीन क्रांतिकारी उत्पाद लॉन्च किए हैं। लॉन्च किए गए उत्पादों में भारत में पहला **FTIR**-आधारित **YAMA** दूध विश्लेषक भी शामिल है। **YAMA** मिल्क एनालाइजर भारत में डिजाइन किया गया पहला फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी **(FTIR)** एनालाइजर है, जो कच्चे दूध की संरचना का तेजी से और सटीक विश्लेषण प्रदान करता है। यह उपकरण दूध में वसा, एसएनएफ और प्रोटीन सामग्री निर्धारित करने और केवल 30 सेकंड के भीतर सामान्य मिलावट का पता लगाने में सक्षम है। इस विश्लेषक की विशेषताओं के कारण यह ग्रामीण स्तर के दूध भंडारण और थोक दूध शीत केंद्रों में क्रांति ला देगा। इस उत्पाद को बाजार में लाने से इसका आयात भी कम करना होगा क्योंकि फिलहाल इसका ज्यादातर आयात किया जाता है। एक अन्य प्रमुख उत्पाद मिल्क फैट फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स (एवरेस्ट जीसी4500) के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी है, जो दूध, दूध उत्पादों और घी की गुणवत्ता को मापने के लिए महत्वपूर्ण फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स की विस्तृत प्रोफाइलिंग प्रदान करता है। यह उपकरण पोषण मूल्य के सही मापन तथा ओथेन्टीसिटी के कारण डेयरी क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

वर्तमान में, फैटी एसिड विश्लेषण और ट्राइग्लिसराइड्स विश्लेषण के लिए दूध वसा के जीसी विश्लेषण के लिए अलग गैस क्रोमैटोग्राफी मशीनों का उपयोग किया जाता है। एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों का विश्लेषण करती है।

इससे मशीनों, सहायक उपकरण, इंस्टॉलेशन और स्पेयर की लागत कम हो जाएगी। इन उत्पादों को हाल ही में हैदराबाद में 50वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मिनेश शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अजीत पटेल ने कहा, हम दृढ़ता से मानते हैं कि इन नवाचारों में न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर डेयरी उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है।

एयर इंडिया ने 180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

नई दिल्ली ।

टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया में भी हाल में 180 से अधिक नॉन-फ्लाइंग स्टाफ की छंटनी कर दी है। कंपनी ने बताया है कि जिन लोगों की नौकरी गई है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और नए सिरे से कौशल निखारने के मौकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे।

एयर इंडिया में 18,500 से अधिक कर्मचारी हैं जबकि ग्रुप एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस में लगभग 6,200 कर्मचारी हैं। बता दें जब टाटा समूह ने एयरलाइन का अधिग्रहण किया था, तब दोनों एयरलाइनों में संविदा कर्मियों सहित कुल 12,085 कर्मचारी थे। इस मामले में एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस प्रक्रिया के दौरान सभी संविदात्मक दायित्वों का सम्मान कर रहे हैं।

कर्मचारियों को भेजे गए एक लेटर के अनुसार छंटनी किए गए कर्मचारियों को एयरलाइन के साथ सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15

दिनों के वेतन के बराबर मुआवजा पैकेज मिलेगा। एयरलाइन ने पहले दो बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं की पेशकश की थी जिसका 2,500 से अधिक कर्मचारियों ने लाभ उठाया था।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि फिटमेंट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, गैर-उड़ान कार्यों में कर्मचारियों को संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

सरकार ने तैयार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति

- ईवी वाहन बनाने वाली कंप नियों के लिए आयात शुल्क 70 से घटाकर 15 प्रतिशत किया

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली वैश्विक कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं। सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है, जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण जोर पकड़ेगा। इस नीति के तहत सरकार ने ऐसे वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए आयात शुल्क मौजूदा 70 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। नई नीति अमल में आने के बाद टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी, किया, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज जैसी दुनिया की नामी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देंगी। ईलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने सरकार से शुल्क में छूट की मांग की थी और नई नीति उसी का नतीजा दिख रही है।

नई नीति के तहत विदेश में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) ई-कार भारत में आयात की जा सकती है। ऐसी कारों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। फिलहाल 40,000 डॉलर से अधिक दाम वाली सीबीयू ई-कार पर 100 प्रतिशत और इससे कम कीमत वाली ई-कार पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब जो नीति तैयार की है, उसके हिसाब से टेस्ला जैसी कंपनियों से सीबीयू ई-कार पर भी 15 प्रतिशत आयात शुल्क ही वसूला जाता है। टुकड़ों या पुर्जों की शक्ल में (सीकेडी) आने वाली कारों पर अभी इतना ही शुल्क लगता है। सीकेडी को देश में लाकर असेंबल किया जाता है। सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठकों में टेस्ला कर घटाने की मांग करती रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार कंपनियां स्वयं उत्पादन करती हैं तो उनके उत्पादों पर कम आयात शुल्क लगेगा।

लेकिन इन कंपनियों को देश में कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इस योजना में वे कंपनियां ही शामिल हो सकती हैं, जो तीन साल के भीतर अपने कारखाने लगाएंगी और पांचवें साल तक उनकी गाड़ियों में कम से कम 50 फीसदी स्थानीयकरण होना चाहिए यानी 50 फीसदी पुर्जे भारत से ही लिए होने चाहिए।

पेट्रोल और डीजल कई राज्यों में पांच रुपए तक मिल रहा सस्ता

नई दिल्ली ।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर 15 मार्च को मिली राहत के बाद देशभर में ईंधन के भाव स्थिर हैं। सरकार ने शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है, वहीं कुछ राज्यों में वैट कम होने से पेट्रोल-डीजल 5 रुपये तक सस्ता मिल रहा है।

शनिवार के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर ईंधन के नए भाव जारी कर दिए हैं। लखनऊ, पटना और चेन्नई समेत अन्य बड़े शहरों में ईंधन का भाव कम हुआ है। हालांकि आज कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल के भाव मामूली रूप से बढ़ भी गए हैं। गोवा, गुजरात, हिमाचल और केरल समेत कुछ राज्यों में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि कुछ प्रदेशों में भाव स्थिर हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 94.71 रुपये और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल 94.80 रुपये और डीजल 87.85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 94.56 रुपये और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.24 रुपये और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 105.48 रुपये और डीजल 92.32 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपये और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

आईपीएल की स्ट्रीमिंग मुफ्त में देखें

मुम्बई । 22 मार्च से शुरु हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबले देश के 10 अलग अलग शहरों में होंगे। इस टी20 लीग मैचों की स्ट्रीमिंग मुफ्त में देखी जा सकेगी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको मुफ्त में एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। आईपीएल में इस बार 74 मैच खेले जाएंगे। इस बार लीग का आयोजन 67 दिनों तक चलेगा। वहीं पिछली बार आईपीएल का आयोजन 60 दिनों का था। वहीं साल 2019 में भी इसी तरह से दो चरणों में आईपीएल के मैच हुए थे। उस समय भी देश में आम चुनाव के कारण आईपीएल के कार्यक्रम अलग-अलग भाग में हुए थे। इस बार दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से जबकि शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे। आईपीएल 2024 का पहला मैच मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2024 मुकाबलों की टीवी पर लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। आईपीएल 2024 मुकाबलों की मोबाइल पर फ्री में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप पर देखी जा सकेगी। इस बार कुल दस टीमें भाग ले रही हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें पहले मैच में रात 8:00 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

मजबूत दिल्ली कैपिटल्स, आत्मविश्वास से भरी आरसीबी के बीच होगी रोमांचक खिताबी भिड़ंत

नई दिल्ली,

अरुण जेटली स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ एक रोमांचक खिताबी भिड़ंत की गवाह बनेगी, जब मेग लैनिंग की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स आत्मविश्वास से भरी स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भिड़ेगी, जिससे यह तय होगा कि कौन रविवार को चमचमाती डब्लूपीएल 2024 ट्रॉफी उठाता है. पिछले साल डब्लूपीएल 2023 में मुंबई से हारकर उपविजेता बनने के बाद दिल्ली के पास अब अपने घरेलू मैदान पर खिताब जीतने का सुनहरा मौका है. उनका प्रभावशाली फॉर्म उन्हें अपना पहला डब्ल्यूपीएल खिताब हासिल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. इसके अलावा, डब्ल्यूपीएल इतिहास में आरसीबी के खिलाफ अपनी सभी चार भिड़ंत में दिल्ली विजेता रही है. प्रतियोगिता में दो हार को छोड़कर, बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दिल्ली की अजेय छवि को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया की कई बार विश्व कप विजेता कप्तान मेग लैनिंग ने आत्मविश्वास के साथ दिल्ली का नेतृत्व किया है, जबकि आठ पारियों में 308 रन बनाए हैं, और उन्हें शीर्ष क्रम में दूसरे छोर से बड़ी हिट शैफाली वर्मा का समर्थन मिला है. इस सीज़न में बल्ले से दिल्ली की सफलता में जेमिमा रोड्रिग्स और एलिस कैप्सी भी रन बनाने वाली प्रमुख खिलाड़ी रही हैं. गेंदबाजी विभाग में, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मारिजैन कप्प और बाएं हाथ के स्पिनर जेस जोनासन ने 11 विकेट लिए हैं, जिससे वे टीम के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गयी हैं. बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव के साथ-साथ तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे और तितास साधु भी डीसी के लिए गेंद से भरोसेमंद खिलाड़ी रही हैं. दूसरी ओर, आरसीबी को प्लेऑफ में प्रवेश करने के लिए उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था, तो उन्होंने हार नहीं मानी और मुम्बई को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. उनकी उम्मीदें फिर से स्मृति, ऋचा घोष और एलिस पैरी, जो 312 रनों के साथ डब्ल्यूपीएल 2024 के लिए रन-स्कोरिंग चार्ट में सबसे आगे हैं, की तिकड़ी पर होंगी . उस रात जब उनकी टीम की बाकी साथी बल्ले से अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, एलिस ने बाउंड्री लगाने से पहले समय लिया और गेंद को नियमित

अंतराल पर अच्छी टाइमिंग के साथ 50 गेंदों पर 66 रनों के साथ शीर्ष स्कोर तक पहुंचाया, जो अंततः आरसीबी को विजयी स्कोर तक पहुंचाने में निर्णायक साबित हुआ. आरसीबी को उम्मीद होगी कि स्मृति, ऋचा, दिशा कसाट और सोफी डिवाइन, जो खराब फॉर्म में हैं, फाइनल में अपनी लय हासिल कर लेंगी.

पाक में दो दशक के बाद खेली जाएगी त्रिकोणीय सीरीज

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें होंगी शामिल

लाहौर ।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा है कि उनकी टीम अगले साल फरवरी में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक अपनी ही धरती पर एक त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी। पीसीबी के अनुसार दो दशक के बाद देश किसी त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्टूबर 2004 में अंतिम बार त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी की थी तब श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान खेलने आई थीं। पीसीबी के अनुसार त्रिकोणीय सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेली जाएगी। पाकिस्तान की टीम को इस एकदिवसीय टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। पाक ने अंतिम बार चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में जीती थी। तब उन्होंने भारत को फाइनल में 180 रन से हराया था।वहीं पीसीबी के नये अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के अध्यक्ष लॉसन नायडू और न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के अध्यक्ष रोजर टूसे से मुलाकात के बाद त्रिकोणीय सीरीज की घोषणा की है। पाकिस्तान ने अंतिम बार साल 2008 में बांग्लादेश में त्रिकोणीय सीरीज में भाग लिया था। इस सीरीज में पाक के अलावा अन्य दो टीमें बांग्लादेश और भारत थीं। अंतिम बार पाकिस्तान ने अक्टूबर 2004 में त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी की थी तब श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान खेलने आई थीं। पीसीबी प्रमुख नकवी ने कहा, पीसीबी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए भी उत्सुक है, जो पाकिस्तान के लिए अपनी धरती पर शीर्ष आठ एकदिवसीय टीमों की मेजबानी करने से जुड़ा है। हमारी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय सीरीज एक रोमांचक घटना होगी और यह लंबे समय के बाद है कि पाकिस्तान इस तरह के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। मैं त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लेने के लिए सहमत होने के लिए न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड का आभारी हूं।

टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और फाइनल में बाधा आई तो रिजर्व दिनों में होगा मुकाबला : आईसीसी

दुबई ।

वेस्टइंडीज और अमेरिकी में जून में होने वाले टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन रखे गये हैं जिससे बारिश आदि के कारण रद्द होने पर मैच इन दिनों रखा जाएगा। रिजर्व दिनों को लेकर फैसला आईसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक के दौरान लिया गया क्योंकि पिछले सत्र में रिजर्व दिन नहीं रखे जाने की कड़ी आलोचना हुई थी, कई टीमों को इससे नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए ही आईसीसी ने गत वर्ष भारत में हुए पुरुष एकदिवसीय विश्व कप के लिए रिजर्व दिन रखा था। बैठक के दौरान,आईसीसी ने पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए खेल की शर्तों को भी मंजूरी दे दी और 2026 संस्करण के लिए योग्यता प्रक्रिया की भी घोषणा की। आईसीसी ने वार्षिक बोर्ड बैठक के बाद कहा कि ग्रुप चरण और सुपर आठ चरण में मैच आयोजित करने के लिए दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम पांच ओवर फेंकने होंगे। नॉकआउट दौर में, एक मैच के लिए दूसरी पारी में कम से कम 10 ओवर फेंकने होंगे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी गई। ये 20 टीमों का टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और इसमें कुल 12 स्वचालित क्वालीफायर होंगे। 2024 संस्करण में शीर्ष आठ टीमें भारत और श्रीलंका के साथ स्वचालित क्वालीफायर के रूप में जुड़ेंगी।

निसांका के शतक से श्रीलंका ने दूसरे एकदिवसीय में बांग्लादेश को हराया

सीरीज 1-1 से बराबरी पर आयी

चट्टोग्राम।

श्रीलंकाई टीम ने दूसरे एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर सीरीज एक-एक से बराबरी पर ल दी है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए श्रीलंकाई टीम को 287 रन का लक्ष्य दिया था जो उसने पाथुम निसांका के शतक से हासिल कर लिया। इस मैच में जीत के लिए मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही पर पाथुम निसांका और चरिथ असलांका ने शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। निसांका ने जहां 114 रन बनाये। वहीं असलांका ने 93 गेंदों पर 91 रन बनाए। इन दोनो के आउट होने के बाद हसरंगा और दुनिथ ने टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। की राह दिखाई।

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरूआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज लिटन दास खाता खोले बिना ही पेवेलियन लौट गये। इसके बाद सैम्य सरकार और कप्तान शान्तो ने पारी को आगे बढ़ाया। सौम्य सरकार ने 66 गेंदों पर 68 रन बनाए जबकि शान्तो 40 रन पर आउट हुए। मध्यक्रम में तौहीद ने नाबाद 96 रन बनाए और स्कोर 286 तक ले गए। इस दौरान मुशफिकुर रहीम ने 28 गेंदों पर 25, मेहदी हसन ने 12, तंजीम हसन साकिब ने 18 तो तस्कीन अहमद ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए। वहीं श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि दिलशान मधुशंका ने 30 रन देकर 2 विकेट लिये। प्रमोद ने भी 72 रन देकर 1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरूआत खराब रही। अविष्का फर्नांडो 0, कप्तान कुसल मेंडिस 16 तो समरविक्रमा 1 रन बनाकर आऊट हो गए पर इसके बाद निसांका और चरिथ असलांका ने पारी को आगे बढ़ाया।

निसांका ने 113 गेंदों पर 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 114 रन बनाए। वहीं, असलांका ने 93 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। जानिथ 9 रन बनाकर आऊट हो गए। तब दुनिथ 15 और वानिंदु हसरंगा 25 ने पारी को संभाला और अपनी टीम को जीत दिला दी। इस सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश जीती थी। ऐसे में अब ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गयी है।

संक्षिप्त समाचार

धोनी आईपीएल के बीच में ही छोड़ सकते हैं कप्तानी : रायडू

नई दिल्ली । पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने कहा है चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के बीच में ही कप्तानी छोड़कर किसी अन्य खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। सीएसके के लिए पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रायुडू का मानना है कि भविष्य को देखते हुए माही आईपीएल के दौरान किसी युवा को चेन्नई का कप्तान बना सकते हैं। पिछले सत्र में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सीएसके का कप्तान बनाया गया था पर लगातार असफल होने के कारण उन्होंने बीच में ही कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद से ही ये जिम्मेदारी धोनी संभाल रहे हैं। उनकी कप्तानी में सीएसके को साल 2023 में पांचवीं बार खिताब मिला था। रायुडू ने कहा ,'इंपैक्ट प्लेयर नियम के जरिए धोनी बीच के ओवरों में किसी और को कप्तानी सौंप सकते हैं। यह साल सीएसके के लिए बदलाव वाला हो सकता है। अगर यह उनका आखिरी साल है , अगर वह कुछ साल और खेलते हैं तो वह कप्तान बने रहेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं चाहूंगा कि वही कप्तान रहें।' धोनी ने हाल ही में फेसबुक पोस्ट में संकेत दिया था कि इस साल आईपीएल में वह नई भूमिका में होंगे। वहीं रायुडू इस सत्र में कमेंटेटर के तौर पर नजर आयेंगे। रायडू ने पिछले साल खेल के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया था।

अब समय बेकार नहीं कर पायेगी गेंदबाजी टीम , स्टॉप क्लॉक नियम होगा लागू

आईसीएकदिवसीय ने दी मंजूरी

दुबई । अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने समय की बर्बादी को रोकने के लिए एकदिवसीय और टी20 में स्टॉप क्लॉक नियम को लाने का फैसला किया है। आईसीसी ने कहा है कि परीक्षण अवधि में सफल होने पर स्टॉप क्लॉक नियम को स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। इस नियम को इसलिए लगाया गया है जिससे कि बीच में होने वाली समय की बर्बादी को रोका जा सके। ये नियम शुरू में दिसंबर 2023 में ट्रॉयल के आधार पर पेश किया गया था। इसे अब टी20 अंतराष्ट्रीय और एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय सहित सभी सफेद गेंद वाले क्रिकेट में लागू करने की सहमति आईसीसी ने दे दी है। स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार फील्डिंग टीम को एक ओवर समाप्त होने के बाद अगला ओवर 60 सेकेंड करीब एक मिनट के अंदर शुरू करना होता है। ओवर समाप्त होते ही स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी और फिर 60 सेकेंड के अंदर टीम को दूसरा ओदवर शुरू करना होगा। वहीं अगर गेंदबाजी करने वाली टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो उन पर पेनल्टी लगती है। इस गलती के कारण फील्डिंग टीमों पर पांच रनों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले उन्हें दो बार चेतावनी भी मिलती है। सभी आईसीसी सफेद गेंद प्रारुप के लिए नियम को लागू किया जाएगा।

बीसीसीआई रणजी खिलाड़ियों के लिए मैच फीस दोगुनी या तिगुनी करे : गावस्कर

मुम्बई ।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों की मैच फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना किया जाना चाहिए। हाल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रणजी खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ायी है पर गावस्कर इसे पर्याप्त नहीं मानते। उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि इसे दुगनी या तिगुनी करे।

गावस्कर ने कहा, अगर रणजी ट्रॉफी की फीस दोगुनी या तिगुनी की जा सकती है, तो अधिक से अधिक खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलना चाहेंगे। साथ ही कहा कि रणजी ट्रॉफी की फीस अधिक होने पर सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलना चाहेंगे। गावस्कर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट चलता रहेगा पर भविष्य में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज अब कम ही होगी। हो सकता है कि हर देश के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज केवल दो या तीन देश ही पांच टेस्ट खेल सकते हैं. गावस्कर ने इसके बाद इंसेटिंव स्कीम का उदाहरण देते हुए कहा, जैसा कि भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने धर्मशाला टेस्ट के बाद कहा था कि इंसेंटिव स्कीम

टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक ईनाम की तरह है। ऐसे में बीसीसीआई से मैं यह अनुरोध करूंगा कि रणजी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए भी कुछ ऐसी ही योजना लाई जाए।

आईपीएल का दूसरा चरण यूएई में रखे जाने की अटकलें

मुम्बई । देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सत्र के दूसरे चरण को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रखे जाने की अटकलें लगायी जा रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक टूर्नामेंट के पहले 21 मैचों का कार्यक्रम ही जारी किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इसी कारण बीसीसीआई अधिकारी अभी यूएई गये हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सभी आईपीएल टीमों ने खिलाड़ियों से अपने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा कि 22 मार्च से शुरु हो रहे आईपीएल का दूसरा चरण देश से बाहर आयोजित किया जा सकता है। बीसीसीआई का कार्यक्रम अगर आम चुनावों की तारीख से टकराता है तो उसके लिए इसका आयोजन देश में करना संभव नहीं रहेगा क्योंकि इस दौरान सुरक्षा सहित कई अन्य सवाल भी उठ जाएंगे। बीसीसीआई ने पहले कहा था कि आईपीएल का आयोजन देश में ही होगा और लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद ही वह दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर पायेंगे। इससे पहले 2009 में भी लोकसभा चुनावों के कारण पूरा आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कराया गया था। इसी प्रकार साल 2019 में टूर्नामेंट का पहला चरण यूएई में करवाया गया था।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रोड्स के नाम हैं सबसे अधिक चार हजार विकेट

लंदन । इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर विल्फ्रेड रोड्स का नाम भले भी क्रिकेट जगत में लोकप्रिय नहीं है पर इस क्रिकेटर के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट हैं। रोड्स ने अपने 32 साल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 4000 से ज्यादा विकेट लिए हैं। वह इस फॉर्मेट में एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने चार हजार विकेट लिए हैं। 1898 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत करने वाले विल्फ्रेड रोड्स ने 1930 तक खेला। उन्होंने 1110 प्रथम श्रेणी मैचों में सबसे अधिक 4204 विकेट लिए। जिसमें एक पारी में 287 बार 5 विकेट भी शामिल हैं जबकि मैच में उन्होंने 68 बार 10 विकेट लिए हैं। विल्फ्रेड ने इस दौरान 185742 गेंदें फेंकी जिसमें उन्होंने 70322 रन दिए। प्रथमश्रेणी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में इंग्लैंड के लेग ब्रेक गेंदबाज अल्फ्रेड पर्सी फ्रीमैन दूसरे नंबर पर हैं. अल्फ्रेड पर्सी फ्रीमैन ने 592 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 3776 विकेट लिए हैं। जिसमें 386 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए वहीं 140 बार मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए। फ्रीमैन ने इस दौरान 154658 गेंदें डाली जिसमें 69577 रन दिये। पारी में 53 रन देकर 10 विकेट उनकी बेस्ट गेंदबाजी रही। इस गेंदबाज ने 1914 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. जबकि 1936 में वह अंतिम बार उतरे। इस सूची में तीसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के ही स्पिनर चार्ली पार्कर 635 मैचों में 3278 विकेट लिए हैं जबकि इंग्लैंड के पूर्व मीडियम पेसर जॉन हर्नी ने 639 मैचों में कुल 3061 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पेरिस ओलंपिक की तैयारियों का अच्छा अवसर मिलेगा : हरमनप्रीत

नई दिल्ली ।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि अगले माह पांच मैचों की सीरीज के लिए होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे से उनकी टीम को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। हरमनप्रीत का मानना है कि आगामी पेरिस ओलंपिक में जीत के लिए उनकी टीम को कई क्षेत्रों में सुधार की जरुरत है। हरमनप्रीत ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उनकी टीम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम ने अंतिम बार 34 साल पहले साल 1980 में मास्को ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। उसके बाद से ही टीम इसके करीब भी नहीं पहुंच पायी। टोक्यो ओलंपिक में हालांकि टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक का लंबा इंतजार खत्म किया था। हरमनप्रीत ने कहा कि अगर हम टीम के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो यह अच्छा है। हम अतिआत्मविश्वास में नहीं हैं पर हम सभी बड़ी टीमों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमारी टीम आत्मविश्वास से भरी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है। इसके अलावा हम किसी अन्य चीज पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। भारतीय टीम ने पिछले साल एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज करने के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था।

इसके बाद उसने एफआईएच प्रो लीग में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम इस लीग में आठ मैच में 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। हरमनप्रीत ने कहा कि प्रो लीग के सभी मैच कठिन थे, लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने इन मैचों से काफी कुछ सीखा और टीम ने काफी सुधार किया। कुल मिलाकर हमने अच्छा प्रदर्शन किया।

हार्दिक को लेकर प्रवीण ने बीसीसीआई पर निशाना साधा, वह चांद से नहीं आया

नई दिल्ली । पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने आईसीसी अनुबंध को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) पर पक्षपात का आरोप लगाया है। प्रवीण ने कहा एक ओर से घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया है। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को अनुबंध सूची में बरकरार रखा है जबकि पंड्या भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण ने तंज कसते हुए कहा कि पंड्या कोई चांद से उतर के नहीं आया है। प्रवीण ने कहा, पंड्या क्या चांद से उतर के आया है। अन्य लोगों की तरह ही उन्हें भी घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। उनके लिए कोई अलग नियम नहीं रखा जा सकता। बीसीसीआई को अपनी इस नीति का कारण भी बताना होगा। साथ ही सवाल किया कि पंड्या केवल घरेलू क्रिकेट में टी20 टूर्नामेंट ही क्यों खेलेंगे? उन्हें टेस्ट और टी20 सहित हर प्रारुप में खेलना होगा। पंड्या ने भारतीय टीम की ओर से छह साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में खेला था। इसके बाद से ही वह टेस्ट मैच से बाहर हैं। वह केवल भारतीय टीम की ओर से टी20 और एकदिवसीय मैच में भाग लेते हैं। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो वह केवल 20 ओवर के मैच में हिस्सा लेते हैं। हाल में ही उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम की ओर से खेला था। पंड्या ने अब तक भारत की ओर से कुल 92 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 1348 रन बनाये हैं। उनका सबसे अधिक स्कोर 71 का रहा है। वहीं गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 92 मैचों की 82 पारियों में कुल 73 विकेट लिए हैं।

11.77 करोड़ रुपये की लागत से डुमस-सुल्तानाबाद में बनने वाली समुद्री कटाव रोधी समुद्री रक्षा दीवार का उद्घाटन हुआ

सूरत ।

शहर के चोरयासी तालुका के डुमस-सुल्तानाबाद में 11.77 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एमएंडआर से आर.टी. का निर्माण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल ने किया. समुद्र-कटाव रोधी दीवार का उद्घाटन किया गया। सूरत सिंचाई विभाग डुमास के तट से आने वाले भारी ज्वार के पानी के कारण गाँव की भूमि और घरों के कटाव को रोकने के लिए 320 से 750 मीटर की सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगा, जिससे लगभग 400 घरों के 25,000 ग्रामीणों को लाभ होगा और सुरक्षा मिलेगी। गांव।

इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से डुमस समुद्र में लगातार आ रहे ज्वार के पानी से गांव में बाढ़ आने से गांव की जमीन का बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है. लेकिन जल्द ही आरसीसी दीवार बनने से ग्रामीणों की मिट्टी कटाव की समस्या दूर हो जायेगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में सीवरेज और पेयजल के लिए विकास कार्य कराए गए हैं. मंत्री ने सूरत के पर्यटकों के लिए करोड़ों की लागत से डुमस बीच के विकास का जिक्र किया और कहा कि पहले चरण का काम चल रहा है. उन्होंने डुमास बीच के विकास से स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोजगार के नये अवसरों के बारे में भी बताया.

आगे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि सिटी फॉरेस्ट का निर्माण वन विभाग के तहत किया जा रहा है और प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से पक्षी पार्क से लेकर मनोरंजन पार्क तक स्थानों को विकसित करने के कार्य का उल्लेख किया. साथ ही, तेजी से विकसित हो रही सूरत में तापी नदी पर रूंध और भाटा के बीच बनने वाले पारंपरिक बैराज के कारण अगले 50 वर्षों तक सूरत में पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी।

इस मौके पर विधायक संदीप भाई ने कहा कि सुरक्षा दीवार के निर्माण से मिट्टी का कटाव रुकने से किसानों को भी लाभ होगा और समुद्र को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा. उन्होंने कहा कि लगभग हर गांव में स्थानीय लोगों के लिए पेयजल और किसानों के लिए सिंचाई के पानी के साथ-साथ सीवरेज सहित सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांठ क्षेत्र के गांवों में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय तंत्र कृतसंकल्प है।

इस अवसर पर महापौर दक्षेशभाई मवानी, स्थायी समिति अध्यक्ष राजनभाई पटेल, जल समिति अध्यक्ष हिमांशुभाई राउलजी, नगरसेवक नेता कैलाशबेन सोलंकी और दीपेशभाई पटेल, सूरत सिंचाई मंडल के कार्यकारी अभियंता (कांकरापार नहर) श्री सतीश पटेल, ड्रेनेज विभाग के कार्यकारी अभियंता बी.के.पठानी, अधीक्षण अभियंता श्री एसबी देशमुख और सिंचाई अधिकारी/कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में निष्पक्ष चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई

सूरत । लोकसभा आम चुनाव-2024 की तारीखों की घोषणा के बाद जिला प्रशासन तंत्र हरकत में आ गया है. चुनाव को लेकर सूरत जिला चुनाव अधिकारी व कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट में नोडल अधिकारियों व सहायक चुनाव अधिकारियों के साथ आपात बैठक हुई. जिसमें चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला सेवा सदन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न विंगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए चुनाव खर्च पर नियंत्रण, विज्ञापन, होर्डिंस हटाने आदि पर चर्चा की गयी. बैनर आदि, मतदाता जागरूकता के लिए प्रभावी संचालन, प्रशिक्षण, ईवीएस। भंडारण कक्ष, हेल्पलाइन शिकायतों, वाहन व्यवस्था, एमसीएमसी की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था कम्प्यूटरीकरण, एसएमएस के संबंध में जांच। संचार योजना, मतपत्र, स्टाफ, विस्थापित मतदाताओं की निगरानी सहित अन्य चुनावी मामलों पर नोडल अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी जिम्मेदार अधिकारी सहयोग करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव को निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की वकालत की. आवेदकों से प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्टिंग की गई तथा सक्रिय दृष्टिकोण दिखाते हुए कर्तव्य निर्वहन हेतु उपयोगी मार्गदर्शन दिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए, एमसीसी ने फ्लाई-स्कोर टीमों को नियोजित करने और शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की प्रणाली, नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों को बंद करने को कहा गया. नोडल अधिकारी को अधिकतम मतदान के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित करने को कहा गया। मतदान के समय दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा मतपत्र वितरित करने को कहा गया।

AM/NS India ने हजीरा में "महिला खेल दिवस" मनाया

सुरत भुमि, हजीरा - सूरत ।

दुनिया के दो मुख्य स्टील उत्पादक, आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के संयुक्त उद्यम आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने मंगलवार को हजीरा में "महिला खेल दिवस" मनाया।

सुवाली बीच पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजीरा के ग्रामीण क्षेत्र से सरपंचों, पंचायत सदस्यों, स्थानीय निवासियों, स्कूल स्टाफ और सरकारी कर्मचारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से 600 से अधिक महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यह पहल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ गुजरात के सहयोग से आयोजित की गई थी।

सभी आयु वर्ग की महिलाओं ने 100 मीटर दौड़ और वॉकथॉन सहित कई गतिविधियों के माध्यम से अपनी खेल भावना का प्रदर्शन किया। नींबू और चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर और गुब्बारा उड़ाने की प्रतियोगिता जैसे कई मनोरंजक खेलों का भी आयोजन किया गया था।

आयोजित सभी खेल के लिए तीन विजेताओं का चयन किया गया और उन्हें उनके प्रयासों के लिए आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक प्रतिभागी को उनकी भागीदारी की सराहना के रूप में विचारशील उपहारों से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर तालुका पंचायत की अध्यक्ष तृप्तिबेन पटेल मुख्य अतिथि थीं। इसके अलावा चेतन पटेल, जिला खेल विकास अधिकारी, तापी जिला, निकिताबेन पटेल, तलाटी सह मंत्री, सुवाली ग्राम पंचायत, रेवाबेन पटेल, सरपंच, दमका गांव, नर्मदाबेन पटेल, उपसरपंच, भटलाई गांव, रीनाबेन पटेल, उपसरपंच, राजगारी गांव और दक्षाबेन पटेल, नवचेतना इंटरनेशनल स्कूल, जुनागाम सहित आगेवान भी उपस्थित थे।

शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित होगा

सूरत।

सूरत राइफल शूटिंग एसोसिएशन 16 से 18 मार्च तक सूरत डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है जिसमें पूरे गुजरात से 250 निशानेबाज भाई-बहनों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सूरत शहर के आईएएस आईपीएस जैसे बड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, राइफल शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आटोमेटिक फोकस शामिल होता है, इसलिए सीखने में इस खेल का महत्व बहुत अच्छा है, और सरकार भी सीओई और एक्सीलेंस जैसे शिविरों का आयोजन करके निशानेबाजों को काफी सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा ऑफिसर जिमखाना में आधुनिक शूटिंग रेंज बनने के बाद निशानेबाजों को काफी सुविधा हुई है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट शूटिंग प्रतियोगिता, राज्य शूटिंग प्रतियोगिता और राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के अलावा हर साल खिलाड़ियों के लिए कई अलग-अलग शूटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

मोर्टिन ने प्रीति जिंटा के साथ लॉन्च किया 'अब रहो बेफिकर' कैम्पेन, नई माताओं को मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों से लड़ने की मिलेगी ताकत

पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी ब्रांडों में से एक, मोर्टिन ने अपने मोर्टिन लिक्विड वेपोराइज़र के लिए मशहूर अभिनेत्री प्रीति जी जिंटा के साथ एक नया कैम्पेन शुरू किया है। यह कैम्पेन एक महिला के लिए उसके मातृत्व के सफर और मां के रूप में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की उसकी ज़िम्मेदारी को प्रदर्शित करेगा। मोर्टिन की मॉस्किटो फाइट टेक्नोलॉजी (MFT*)की मदद से मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों के खतरे से उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, इसी जानकारी के साथ 'अब रहो बेफिकरU' कैम्पेन नई माताओं को निडर होकर जीने के लिए प्रोत्साहित करता है।

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियाँ फैलाने वाले मच्छर आज एक बड़ा खतरा हैं। मच्छर जनित बीमारियों के बारे में बढ़ते डर और चिंता के कारण, माताएं अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए लगातार बेहतर और अधिक प्रभावी समाधान ढूंढ रही हैं। मोर्टिन की एमएफटी* (मच्छर से लड़ने की तकनीक), अपनी सक्रिय तेजी से रिलीज होने वाली संरचना के माध्यम से, अपनी बेजोड़ प्रभावशीलता और सुविधा के साथ माताओं को सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सफलता प्रदान करती है। यह तकनीक सभी नई माताओं के लिए समर्थन के स्तंभ के रूप में खड़ी है और दस बीमारियों तक फैलाने वाले मच्छरों से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एक हालिया अभियान में, मोर्टीन माताओं को मच्छर जनित बीमारियों के डर के बिना मातृत्व की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और आश्वासन देता है - अब रहो बेफिकर।

अभिनेत्री और अभियान राजदूत प्रीति जी जिंटा ने एसोसिएशन के बारे में कहा, "एक मां के रूप में, मैं अपने बच्चों को उन छोटे लेकिन घातक मच्छरों सहित सभी खतरों से बचाने की हमारी बहुमूल्य जिम्मेदारी को पहचानती हूं। मोर्टिन की मच्छर लड़ाई जहां प्रौद्योगिकी* जीवन को पीछे धकेलती है, वहीं यह जीवन पर भी ध्यान केंद्रित करती है माताओं को निडर होकर मातृत्व अपनाने के लिए सशक्त बनाने पर। तो, आइए 'अब रहो बेफिकर' जीवन अपनाएं - यह जानकर चिंता मुक्त रहें कि हमारे घर हमारे प्यार और मोर्टिन की सुरक्षा से ढके हुए हैं।"

रेकिट के स्वच्छता प्रभाग, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विपणन निदेशक, सौरभ जैन ने कहा, "मोर्टिन में, हम अपने प्रियजनों को मच्छर जनित बीमारियों के खतरों से बचाने के दौरान परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। जैसे ही हमने अपना नवीनतम अभियान शुरू किया, हम इस चल रही लड़ाई में माताओं की अपरिहार्य भूमिका को उजागर करने में गर्व के साथ खड़े हैं। मोर्टिन की मॉस्किटो फाइट टेक्नोलॉजी* के माध्यम से, हम युवा माताओं को मच्छर जनित बीमारियों से निडर बनाने के लिए सर्वोत्तम समाधान प्रदान करने के अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। यह पहल हर जगह की माताओं को अटूट आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ मातृत्व की यात्रा को सही दिशा में ले जाने के लिए सशक्त बनाती है।"

भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ओटीसी एंटेसिड ब्रांड इनो ने भारत में इनो च्यूई बाइट्स का लॉन्च किया

हेलीऑन (तत्कालीन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर) के अग्रणी डाइजेस्टिव ब्रांड, इनो ने अपनी तरह का पहला चबाने वाला एंटेसिड, 'ENO च्यूई बाइट्स' पेश किया है, जो दो स्वादिष्ट फ्लेवर, टैंगी लेमन और ज़ेस्टी ऑरेंज में उपलब्ध है।

इनो पाँच दशक से ज्यादा समय से लाखों लोगों का एक भरोसेमंद साथी है, जो एसिडिटी से तुरंत राहत देता है। नए इनो च्यूई बाइट्स ग्राहकों की मुख्य ज़रूरत को पूरा करते हैं, और सुविधा एवं आसानी से उपलब्ध हैं। अब चाहे एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, रेस्टोरेंट हो या मॉल, किसी भी जगह एसिडिटी महसूस होने पर बस ये नए स्वादिष्ट चबाने वाले बाइट्स चबाएं और इनो के भरोसे के साथ तेज़ी से एसिडिटी दूर भगाएं।

इस लॉन्च के बारे में कैटेगरी लीड-डाइजेस्टिव हेल्थ, श्री किशलय सेठ ने कहा, "मॉडर्न ज़िंदगी में अक्सर घर से बाहर खाया जाता है, जिससे एसिडिटी भी ज़्यादा होने लगी है। इसलिए एसिडिटी को दूर करने का एक आसान तरीक़ा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। नए इनो च्यूई बाइट्स स्वादिष्ट, चबाने वाले हैं, और इन्हें लेना आसान है। इनके लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनो की विश्वसनीय राहत हर जगह और हर समय ग्राहकों के साथ रहती है।"

नए च्यूएबल फॉर्मेट में श्रद्धा के लॉन्च के बारे में मार्केटिंग हेड, मिस अनुरिता चोपड़ा ने कहा, "डाइजेस्टिव केयर में लीगेसी ब्रांड की अपनी विरासत के साथ ENO अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता है। ENO च्यूई बाइट्स आसान फॉर्मेट में ग्राहकों की दैनिक सेहत सुधारने में मदद करने और इनोवेशन के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम एसिडिटी से तुरंत आराम देना चाहते हैं, इसलिए हमने ENO च्यूई बाइट्स पेश किए हैं, जो ज़्यादा आसानी से चबाकर एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है। ENO च्यूई बाइट्स एसिडिटी भगाने का आसान तरीका पेश कर रहे हैं, और साथ ही ब्रांड के भरोसे एवं विश्वसनीयता को भी मजबूत बना रहे हैं।"

नए लॉन्च एवं संचार के बारे में ओगिल्वी इंडिया (उत्तर) की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, मिस रितु शारदा ने कहा, "भारतीयों को खाना पसंद है। हम कहीं भी, कभी भी खाना पसंद करते हैं। इस वजह से एसिडिटी भी कहीं भी और कभी भी हो सकती है। एसिडिटी चाहे कभी भी हो, श्रद्धह च्यूई बाइट्स आपको शानदार फॉर्मेट में जीवन का आनंद लेने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। अपने नए अभियान में हम यही दिखा रहे हैं, जिसमें एक बुद्धिमान माँ ENO च्यूई बाइट्स की मदद से एसिडिटी से तुरंत राहत प्रदान करती है।"

"भीड़" के एक्सक्लूसिव प्रीमियर के साथ सिनेमाई हदें तोड़ने जा रहा है एंड एक्सप्लोर एचडी

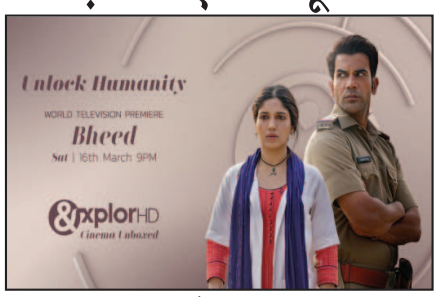

एंड एक्सप्लोर एचडीचैनल एक बेमिसाल अनुभव का वादा करता है जो दर्शकों के लिए सिनेमा को अनबॉक्स करेगा। यह चैनल अब शनिवार, 16 मार्च को अभूतपूर्व फिल्म "भीड़" का प्रीमियर करने जा रहा है। यह हर फिल्म प्रेमी की मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करेगा जो कि अनरूटीन, अनपेक्षित और अनफॉर्मूला है। चैनल के पास फिल्मों का एक विशाल भंडार है जो कहानी कहने की अभूतपूर्व खोज करता है।

फ़भीड़फ़ कहानी कहने, सिनेमाई हदों से पार निकलने और कहानी की सीमाओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि पर आधारित एक अनसुनी कहानी पर रौशनी डालती है। इसकी कहानी एक समर्पित पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आती है, जिसे संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को सीमा पार करने से रोकने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा जाता है। हालांकि, अधिकारी की यात्रा एक अनजाना मोड़ लेती है क्योंकि वो अपने चारों ओर पूर्वाग्रह और गहरे दर्द को देखता है, जिससे उसका कर्तव्य इंसानियत के लिए एक भावुक लड़ाई में बदल जाता है #UnlockHumanity। जाने-माने निर्देशक अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पंकज कपूर, राजकुमार राव, भूमि पेडणेकर, दीया मिर्जा और कृतिका कामरा जैसे शानदार कलाकार हैं।

एंड एक्सप्लोर एचडीपर प्रीमियर होने जा रही "भीड़" को लेकर राजकुमार राव अपना उत्साह जाहिर करते हुए कहते हैं, "यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है; यह अनसुनी और अनजानी कहानी कहने का एक जरिया है। एंड एक्सप्लोर एचडीहमारी अनूठी यात्रा के लिए एकदम सही जगह है, और मैं वास्तव में इस अनुभव को सभी के साथ साझा करने के लिए रोमांचित हूं। 'भीड़' कोई आम फिल्म नहीं है; यह एक खोज है, मानदंडों के लिए एक चुनौती है, और मुझे दर्शकों के इस खास कहानी में गहरे उतरने का इंतजार है।"

दीया मिर्ज़ा ने कहा, "मुझे यकीन है कि अगर हम धरती माता की रक्षा करते हैं, तो वो भी हमारी रक्षा करेगी। भड़, कोविड -19 महामारी के दौरान इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों को गहराई से दर्शाती है, और एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनना हमेशा से पुरस्कृत और स्फूर्तिदायक रहा है जो ऐसे गहन विषयों को संबोधित करती है। महामारी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हमें अपने जीने, उत्पादन, निर्माण और उपभोग के तरीके को बदलना होगा। इस फिल्म की शूटिंग एक भावनात्मक यात्रा रही है, किसी भी चीज़ से कहीं ज्यादा परिवर्तनकारी और मैं एंड एक्सप्लोर एचडी के दर्शकों के लिए इंसानियत और हौसले की इस खोज को शुरू करने के लिए उत्सुक हूं।"

निर्देशक अनुभव सिन्हा ने एंड एक्सप्लोर एचडी पर प्रीमियर के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "हमारे लिए, 'भीड़' एक फिल्म से कहीं ज्यादा है; यह इंसानी अनुभव की खोज है। मुझे सचमुच विश्वास है कि एंड एक्सप्लोर एचडी पर इसके प्रीमियर के साथ, हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएंगे, जो फिल्म के सार को समझ सकेंगे। भीड़ के कलाकारों के साथ शूटिंग करना वाकई एक सुखद एहसास था, जिससे यह पूरी टीम के लिए यादगार बन गया। अंत में, नई कहानियों के प्रति एंड एक्सप्लोर एचडीका समर्पण इसे बनाने के हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह हमारे लिए बिल्कुल सही मंच है।"

एंड एक्सप्लोर एचडी दर्शकों को एक बेमिसाल सिनेमाई सफर पर जाने और शनिवार, 16 मार्च को 'भीड़' का प्रीमियर देखने के लिए आमंत्रित करता है।

कामरेज तालुका के गांवों जोखा, मकना, अलुरा, विहान, दिगस, ननसद और चोर्यासी में 8 करोड़ रुपये विकास कार्यों का उद्घाटन किया

सूरत। शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया द्वारा कामरेज तालुक के चार गांवों जोखा, मकना, अलुरा, विहान, डिगस, नंसद और चोर्यासी में विभिन्न योजनाओं के तहत 8 करोड़ रुपये से अधिक की 108 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। छात्रों को आराम से अध्ययन करने के लिए आधुनिक स्कूल परिसर और शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण प्रदान करना। विकास परियोजनाएं आधिकारिक तौर पर शुरू की गईं।

कामरेज तालुका के जोखा गांव में 98 लाख रुपये की लागत से जोखा प्राइमरी स्कूल की सात कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, 1.34 करोड़ रुपये की लागत से मकना गांव में प्राथमिक विद्यालय की 10 कक्षाएं, विहान गांव में 1.34 करोड़ रुपये की लागत से। प्रा. की लागत 41 लाख रु. स्कूल की तीन कक्षाएं, 1.40 करोड़ रुपये की लागत से ननसद गांव में निजी स्कूल की 10 कक्षाएं और 2.75 करोड़ रुपये की लागत से ननसद माध्यमिक विद्यालय का खतमुहूर्त और चोर्यासी गांव में दो कमरे के स्कूल का खतमुहूर्त। राज्य मंत्री द्वारा 28 लाख रु. इसके अलावा अलुरा गांव में 66 लाख रुपये की लागत से 55 घर, डिगास गांव में 25 लाख रुपये की लागत से 21 घर भी मंत्री ने सौंपे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादक: संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोन: 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)